हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 16 मार्च 1979

पृश्ठ संख्या

होली की बधाई	(9) 1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(9) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(9) 27
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(9) 33
राज्यपाल का संदे ा	(9) 43
वक्तव्य :– कृशि मंत्री द्वारा कृशि उपज की कीमतों के बहुत ज्यादा गिरने सम्बंधी	(9) 44
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान बिल, 1979	(9) 47

हरियाणा विधानसभा

भुक्रवार, 16 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

होली की बधाई

श्री अध्यक्षः साहेबान, पहले तो मैं सब माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से होली की भुभकामनाएं पे ा करता हूं।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): हम भी अपने ओर से आपको भुभ कामनाएं पे ा करते हैं।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं भी आपको बधाई देता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः हम सारे अपोजी ान वाले भी आपको बधाई देते हैं।

Mr. Speaker: Thank you.

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान अब सवाल होंगे।

Setting up of Industries in Mewat Area

***913. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to set up industries with the assistance of Government for development of Mewat are in Gurgoan ?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): जी हां।

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने मेरे प्र न के उत्तर में जवाब दिया है कि हम मेवात क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन कौन से उद्योग होंगे और कब तक वहां पर स्थापित हो जायेंगे ?

डाक्टर मंगल सेनः स्पीकर साहब, इन्होंने यह पूछा था कि क्या गुडगांव के मेवाल क्षेत्र के विकास के लिये सरकार की सहायता से उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है तो उसके जवाब में मैंने कह दिया 'हां' है। अब आप ही देखिये इन्होंने यह प्र न पूछा है कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन है, फिर इनका यह सवाल प्रासंगिक है ?

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि वहां पर कौन कौन से उद्योग लगाने का विचार है ?

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आपने सवाल पूछा था उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगायेंगे तो आप नोटिस दें, जवाब आ जायेगा।

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं माननीय स्वामी जी और समूचे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेवात के क्षेत्र के विकास के लिये फिरोजपुर झिरका में औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। अभी हमने वहां एक सर्वे करवाया था। वहां पर सीमेंट, पाईप्स, प्लास्टिक इंजीनियरिंग गुडज, कैमिकल्ज, दाल प्लांट, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मिनीएचर बल्बज और एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस आदि का सामान बनाने का स्कोप है। स्पीकर साहब, इसके लिये सरकार वहां पर 8–10 एकड जमीन एक्वायर करने के लिये विचार कर रही है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे जो हमारे 5–7 गांवों में अभी उत्साह बढा कर आये हैं, क्या उस उत्साह को पूरा कर देंगे ?

श्री अध्यक्षः उत्साह बढाने की बात नहीं, यहां पर तो इंडस्ट्रीज का सवाल है।

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर मेरे माननीय सदस्य इस बात संतुश्ट हों कि हम उनका उत्साह बढाते रहें तो वे आगे बढते जायेंगे और हम निरन्तर उनका उत्साह बढाते रहेंगे।

चौधरी हर स्वरूप बूराः माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि 8–10 एकड एरिया एक्वायर करने जा रहे हैं तो जिन लोगों की वह जमीन एक्वायर करेंगे क्या उकनो मार्किट वैल्यू के हिसाब से कम्पनसे ान दिया जायेगा।

डाक्टर मंगल सैनः वह तो नियम बने हुए हैं उनके मुताबिक होगा।

श्री अध्यक्षः जमीन की वैल्यू तो मेरे ख्याल में रैवेन्यू अथोरिटीज फिक्स करती है।

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय जी को यह बताना चाहता हूं कि किसानों को जो उनकी जमीन की कीमत मिलती है, यह बहुत कम मिलती है, उन्हें कम से कम मार्किट वैल्यू तो मिलनी चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

कंवर राम पाल सिंहः मन्त्री महोदय ने अभी यहां पर बताया है कि गुडगांव में सर्वे करवाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है, अगर मिल चुकी हो तो कब मिली है और कब तक उस पर कार्यवाही करेंगे क्योंकि इन्होंने यह कहा है कि अभी विचाराधीन है ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मूल प्र न में तो यह कहीं नहीं पूछा गया है कि सर्वे रिर्पोट आयी है या कब तक आयेगी। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह भीघ्राति ीघ्र पूर्ण हो जायेगी।

चौधरी पीर चन्दः क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन एक्वायर करते जा रहे हैं, वइ उसे कहां पर सूटेबल समझते हैं ?

श्री अध्यक्षः उन्होंने बता दिया है कि फिरोजपुर झिरका में औद्योगिक क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। वे किसी गांव का नाम नहीं बता सकते कि कहां वे सुटेबैल समझते हैं।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने पिछले ही दिनों किसी हलके को बैकवर्ड घोशित करने के लिए क्राइटेरिया बताया था मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो हलके यह क्राइटेरिया को पूरा करते हैं क्या उन हलाके को बैकवर्ड घोशित किया जायेगा ?

डाक्टर मंगल सैनः यह तो इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्षः हां, यह संबंधित नहीं है।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या साल्हावास जो एक बैकवर्ड एरिया है, में भी उद्योग स्टार्ट किये जायेंगे ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय राव राम नारायण जी की सेवा में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि गत वर्श से केन्द्रीय सरकार ने उस क्षेत्र को पिछडा हुआ क्षेत्र घोशित कर रखा है। अभ तक वहां पर कोई एन्टरप्रैन्योर उद्योग स्थापित करने के लिये नहीं आया। हम तो यह चाहते हैं कि वहां पर उद्योग लगें। कोई आगे तो आये हम उसको 15 प्रति ात सबसिडी गवर्नमैंट आफ इंडिया से लेकर देंगे।

Criminal/Civil cases in the State

***1031. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the arrears of criminal, civil cases/appeals before Magistrates, Sub-Judges/Sessions, District Judges in the State as on 31st December, 1978;

(b) the number of above classes of cases/appeals decided by the Courts during from 1st January to 31st December 1978;

(c) the number of criminal, civil cases/appeals instituted/preferred before Courts in the State during the period mentioned in part (b) above;a nd

(d) the number of persons challanged/bound down in security proceedings in the State during the period mentioned in part (b) above ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) से (डी)– अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

STATEMENT

Name of the Court	Part (a) Cases pending on 31-12-78 (in terms of units)			Part (b) Cases/Appeals decided during 1st January to 31 December, 78 (in units)			Part (c) Cases/Appeals decided during 1st January to 31 December, 78 (in units)			Part (d) No. of persons challanged- 36685- do- bound down- 1254
	Crimia nal	Civil	Appeals	Crimia nal	Civil	Appeals	Crimia nal	Civil	Appeals	
Sub Judges- Cum- Judicial - Magistra es	35064	3640 9	825 (With Senior Sub- Judges)	53530	51909	5107 (With Senior Sub- Judges)	52579 ½	59627 ½	2622½ (With Senior Sub- Judges)	
District /	2914	1156 1	454¾ (Crimina	8809¼	21046 ¾	1836½ (Crimina	7085¼	15235 ¼	1070½ (Crimina	

Additional Distrct & Sessions Judges			ls) 4175 (Civl)			ls) 5439(Civl)			ls) 6747(Civl)	

श्री भाम ोर सिंहः मन्त्री महोदय ने जो सूचना हाउस मे दी है उसके मुताबिक 31—12—1978 तक 86,000 मुकद्दमें ऐसे हैं जो हरियाणा की सुबाडिनिट कोर्टस में पैंडिंग हैं। इस तादाद को देखते हुए, जो इतने एरियर्ज इकट्ठे हो रहें हैं, इनको कम करने के लिये वे क्या उपाय सोच रहे हैं ?

चौधरी भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी 28 पोस्टें और भरने के लिये हमने एच0पी0एस0सी0 को लिखा हुआ है। इसके अलावा चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक स्टेट लैवल पर कमेटी बनाई हुई है जो इनकी प्रोग्रैस को रिव्यू करेगी।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्र न के पार्ट सी के जवाब में जो फिगर्ज दी हैं, उसके मुताबिक यह पोजी ज्ञन है कि सब जज—कम—जुडीि ायल मैजिस्ट्रेटस की कोर्टस में 52500 क्रिमिनल केसिज पैंडिंग हैं और 59600 सिविल केसिज पैंडिग हैं, क्या इन केसिज में इन्क्रीज होने की वजह इन्स्टीच्यू ान ज्यादा हो गइ है या और कोई खास वजह है ? (व्यवधान) मैं प्राइवेट मुकद्दमों की इन्फर्मे ान पूछ रहा हूं। मन्त्री महोदय यह बतायैंगें कि यह जो लिटीगे ान में इन्क्रीज हुई है, क्या यह ला एण्ड आर्डर की पोजी ान खराब होने की वजह से तो नहीं है ?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, यह खुद तो लोगों कों भड़काते हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट मैंने इनके प्र न के उत्तर में दी है अगर उसको गौर से पढें तो उससे यह जाहिर होता है कि सिविल अपील्ज की तादाद पहले से रिडयूस हुई है। जैसे मैंने पहले ही जवाब दिया है कि हम 28 पोस्टें जल्दी ही भरने जा रहे हैं और इसके अलावा हमने स्टेट लैवल पर एक कमेटी बनाई हुई है जो इन केसिज की प्रोग्रैस को रिव्यू करेगीं

श्री भाम ोर सिंहः इन्क्रीज की वजह क्या है ?

श्री अध्यक्षः वह तो कहते हैं कि डिक्रीज हुए हैं (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सै ान जजिज के पास 1–1–1978 को सिविल केसिज जो पैंडिंग थे वह थे 17372½ जो इंस्टीच्यूट हुए डयूरिंग दी ईयर वे हैं 11561 इनमें से 15235 केसिज की डिस्पोजल हुई और इस समय केवल 21046 पैंडिंग हैं। इसी तरह से क्रिमिनल केसिज के बारे में पोजी ान यह है। कि 4635 केसिज तो पैंडिंग थे इंन्स्टीच्यूट हुए डयूरिंग दी ईयर 7685 और डिस्पोजल हुई है 88091¼ की। इस समय 15235 केसिज पैंडिंग हैं।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आजकल मुकद्दमों में 8–9 महीने के बाद की तारीखें दी जाती हैं क्या उसका कारण यह तो नहीं है कि वहां पर जजों की तादाद कम है, अगर है तो क्या नये

जजिज भर्ती करने का विचार रखते हैं और वे कब तक भर्ती कर लिये जायेंगे ताकि लोगों का काम सुचारू रूप से चल सके और लोगों को इतनी लम्बी लम्बी तारीखें न मिलें ?

चौधरी भोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया है कि 28 पोस्टें भरने के लिये स्टैप्स लिये जा रहे हैं जब भी वे भर्ती करेंगे उनको लगा दिया जाएगा।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि 28 सब जतिज लगा रहे हैं इसके लोयर कोट्रस में तो केसिज ऐक्सपीडाइट हो जायेंगे लेकिन सै ान लैवल पर केसी जल्दी ऐक्सपीडाइट नहीं होंगे। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जींद, सिरसा और सोनीपत के अंदर सै ान डिविजन कायम करने का सरकार कोई इरादा है और अगर है तो वह कब तक ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, इसके बारे में सीधा जवाब तो यह है कि अभी कोई विचार नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो य है कि 28 सब जतिज अप्वांट करने से लोयर कोर्टस का काम तो ऐक्सपीडाइट हो जाएगा लेकिन जो ऐपीलैट वर्क है वह स्टैंड स्टिल हो जाएगा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसको दूर करने का सरकार का कोई विचचार है ?

श्री अध्यक्षः सवाल का जवाब तो दे दिया गया है कि अभी कोई विचार नहीं है।

श्री भाम ोर सिंहः क्या मन्त्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि सै ान लैवल पर काम को ऐक्सपीडाइट करने का सरकार को कोई इरादा नहीं है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान यह है कि पिछले वर्शों में काफी बढ़ौतरी हुई है। 1975 में सै ान जजिज छः थे, जबकि अब सै ान जजिज और एडी ानल जजिज की पोस्टें 21 हो गई हैं। इसी तरह 1975 में सब जजिज 38 थे और इस समय 49 हैं।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, जींद में सै ान डिविजन के बारे में एक सवाल पीछे पूछा गया था और क्या मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जींद में सै ान डिविजन होगा लेकिन अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि अभी सै ान डिविजन खोलने का कोई विचार नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दोनों बातों में से कौन सी ठीक है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने यह कहा है कि अभी विचाराधीन नहीं है परन्तु कभी भी विचाराधीन हो सकता है।

***1119. Rao Ram Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether garlands of currency notes are offered to him on his visits to villages while on tour of the State;

(b) whether he announces the total amount so received by him in each town;

(c) where does such money go to and the manner in which this amount is spent; and

(d) the amount of money thus received by the Chief Minister in his recent tour of Kurukshetra district ?

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उस रुपये में उतना ही रुपया सरकार की तरफ से मिला कर मु तरक्कार कामों के लिये सम्बंधित पंचायतों को दे दिया गया है।

(घ) 11.2.1979 से 13.2.1979 तक जिला कुरुक्षेत्र में मैंने 18 गांवों का दौरा किया था और 38826 रुपये की रकम मुझे पे ा की गई थी और मैंने यह रकम राव साहब के बहुत मेहरबान दोस्त की तरह घर में नहीं रखी बल्कि उतनी रकम और साथ मिला कर वह रकम गांव वालों को दे दी थी।

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, इस लोकतान्त्रिक ऐज में भेंट वसूल करना कोई अच्छी बात नहीं लगती। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने के कृपा करेंगे कि इस प्रैक्टिस को बंद करने का उनका कोई विचार है ?

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, इसी वास्ते मैंने भेंट वसूल करने का जो तरीका है वह बदल दिया है क्योंकि लोकतान्त्रिक ऐज में डिवल्पमैंट सबसे जरूरी काम है। मैं यह नई रिवायत डालना चाहता हूं ताकि अगर कहीं राव साहब को कभी मौका मिल जाए तो वह पहले की तरह अपने पास न रखने की रिवाायत भुरू कर सकें इसीलिये साथ ही साथ वह रकम लोगों की तरक्की के लिये दे रहा हूं ताकि यह रिवाज पडे और लोग अपने आप कोि ा ा करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा चन्दा पे ा करेंगे उतना ही तरक्की के कामों के लिये सरकार मैंचिंग ग्रांट के रूप में रुपया देगी और हमें इसमें काफी कामयाबी हुई है।

श्री भले रामः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आपसे पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब थे और इस प्रकार से माला लेते थे क्या वे इसी तरह से करते थे जैसे आप करते हैं ?

श्री अध्यक्षः यह तो आप उनसे पूछ लीजिए।

***894. Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the fertilizer which is imported from the foreign countries is packed in inferior quality bags, thereby causing deficiencies in the net weight of the fertilizer; and

(b) whether the State Government has approached the Central Government for ensuring that fertilizers in bags of inferior quality are not imported to avoid losses to the farmers in the State ?

कृशि मंत्री (ब्रिगडियर रण सिंह): (ए) तथा (बी) स्पीकर साहब, जो खाद हम दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं वह बैग जिस समय बंद होते हैं वे ठीक क्वालिटी के होते हैं लेकिन उनकी चार पांच जगहों पर हैंडलिंग होती है तो कुछ बैग खराब हो जाते हैं और हमने यह कायदा बना दिया है जिससे उन बैग्ज को रिबैगिंग किया जाता है ताकि किसानों को नुक्सान न हो।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, जो खाद खराब हो जाता है वह खाद इकट्ठा हो जाता है और इतना सख्त हो जाता है कि उसको हथौडों से तोडना पडता है और फिर उसको तोड तोड कर दूसरे थैलों में भरा जाता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सच है ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: स्पीकर साहब, हो सकता है कि कोई खाद जो बहुत खराब हो और उसको स्टारे किय जाए और

खासतौर से उस पर बारि ा गुजर जाए तो ऐसी नौबत आ सकती है।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि जो पुरानी खाद होती है उसको रिबैगिंग करके दुबारा तैयार किया जाता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नौलिज में यह बात है कि रिबैगिंग करने के बाद वजन कम रहता है, इसका क्या कारण है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, हमने बडी सख्त इंस्ट्रक ांज दी हुई हैं कि कोई भी ऐजेन्सी या डीजर कम खाद नहीं बेच सकता। अगर कोई इस तरह की ि ाकायत है तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर को बताएं। पहले तो उसका लाईसैंस उसी रोज खत्क कर दिया जाएगा और अगर जरूरत हुई तो उसको कोर्ट में भी ले जाया जाएगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि खाद के बोरों पर सील होने के बावजूद भी उनका वजन कम होता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर ऐसे केसिज उनके नोटिस में लाए जाएं तो उस डीलर या कम्पनी के खिलाफ कोई एक ान लिया जाएगा ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, हैफेड जो खाद सप्लाई करती है उसके हर बैग में पांच से दस के0जी0 खाद कम होती है और यह बात इस महीने की 13 तारीख की ग्रिवेन्सिज कमेटी में उन लोगों ने मानी है। इससे पहले भी इस तरह की ि ाकायत की गई थी। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका कोई इलाज करने का कोई विचार है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, इसका इलाज बहुत आसान है। अगर इस तरह का कोई केस है तो हमारा डिप्टी डायरेक्टर जो जिले में होता है या तहसील में जो अफसर होता है उसको बताया जाए। उसी वक्त कार्यवाही की जाएगी। उसका लाइसैंस खत्क कर दिया जाएगा और जरूरत हुई तो उस पर मुकद्दमा भी चलाया जाएगा।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, जो बात मैंने कही है वह ग्रिवेन्सिज कमेटी में मानी हुई है और यह बिल्कुल ठीक बात है।

ब्रिगेडियर रण सिंहः आप लिखकर दें और अगर उसके खिलाफ ठीक ऐक ान न लिया जाए तो आप मुझे बताएं। ऐक ान लिया जाएगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, कैथल तहसील में खुल्लम खुल्ला युरिया खाद ब्लैक में बिक रहा है और इस बात की ि ाकायत कैथल की ग्रिवेन्सिज कमेटी में महकमें

वालों को की गई है और यह भी उनको बताया गया है कि एक बोरे में सात आठ किलो खाद कम होता है। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः इस बारे में जवाब दिया जा चुका है कि जो ि ाकायत है उसको लिखकर दें, उस पर कार्यवाही की जाएगीं

श्री जय नारायणः स्पीकर साहब, जो पुरानी खाद हो जाती है किसान को उसी रेट पर दी जाती है। क्या मन्त्री महोदय का उस पुराने खाद के रेट में कुछ कटौती करने का विचार है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, पहले की बात तो मैं कह नहीं सकता लेकिन आजकल खाद की हमारे यहां भाोर्टेज रहती हैं बडी मु ि कल से डिमांड पूरी कर पाते हैं उसको अगर ठीक तरह से स्टोर किया जाएग और छः महीने गुजर भी जाएं तो कोई नुक्सान नहीं है लेकिन उसकी स्टोरेज ठीक होनी चाहिए। स्पीकर साहब, चौधर उदय सिंह दलाल ने एक सवाल पूछा था उसका जवाब मैं देना चाहता हूं और उनके दिल और दिमाग से यह निकालना चाहता हूं कि फैक्टरियों से या बाहर से कम वजन के कट्टे नहीं मिलते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सी दफा खाद बाहर से आती है और उसको रिबैगिंग करने में कमी हो जाती है तो उसका पैसा गवर्नमैंट आफ इंडिया देने का मान चुकी है। मैं यह नहीं सकझता कि हमारे आदमी अपने आदमियों को क्यों नुक्सान पहुंचायेंगे। खाद की डिस्ट्रीब्यू ान का काम ए0सी0आई0

के पास है हैफेड के पास है और वेयर हाउसिंह के पास है। कई दफा जब पीक सीजन होता है तो खाद ज्यादा आ जाती है। हमें उसको रिबैग करने का टाइम नहीं मिलता जो अच्छे कट्टे हैं उनको दे देते हैं और जो खराब होते हैं उनको रिबैग करते हैं और जो कमी होती है उसका पैसाव गवर्नमैंट आफ इंडिया देती है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अगर किसी एजेंसी वाले की खाद की बोरियों का वजन कम होगा तो उस ऐजेन्सी का चालान किया जाएगा और उसका लाईसैंस भी कैंसल कर दिया जाएगा। मै। आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की तरफ से जब खाद ऐजैन्सियों को सप्लाई की जाती है तो वे कट्टे सील्ड होते हैं और जब वजन कम निकलता है तो सरकार सारी जिम्मेवारी डीलर्ज पर डाल देती है, इसकी जिम्मेवारी डीलर्ज की बजाये सरकार अपने पर क्यों नहीं डालती ? क्या मंत्री महोदय इस बारे में रो ानी डालेंगे ?

श्री अध्यक्षः मांगेराम जी, जो खरीद करते हैं, उनको उसी वक्त इसकी जांच कर लेनी चाहिए, अगर खाद कम हो तो उसको चाहिए कि जिस फर्म से खाद ली गई है, उसे वापिस कर दे।

श्री सुमेर चन्द भट्टः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन सेल्ज डिपोज से खाद की कमी की ि ाकायत आती है, क्या सरकर उन्हीं जगहों पर तराजू का प्रबन्ध करने का विचार रखती हे ताकि जिस किसान को किसी प्रकार का भाक हो तो वे उसी वक्त मौके पर ही खाद को तुलवा कर चैक कर सकें और आगे से इस प्रकार की कोई ि ाकायत न रहे ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किया जा रहा है। अगर किसी जगह पर ऐसा नहीं हो रहा है तो आनरेबल मैम्बर हमारे नोटिस में लाएं, हम एक ान लेंगे। दूसरी बात गुप्ता जी ने सीलड की बाबत कही, वह गलत बात है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर महोदय के नोटिस में है कि जितनी खाद की प्राइवेट ऐजैंसियां हैं, वे सारी की सारी भाहर वालों को दे रखी हैं और जिन लोगौं काच खाद वगैरह से किसी किस्म का कोई सम्बंध नहीं है और रि बैगिंग के टाईप पर बढौतरी औ घटोतरी की जितनी बात होती है वे सारी की सारी प्राईवेट एजैन्सियों वाले ही करते हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार आगे के लिये कोई ऐसा प्रबंध करने का विचार रखती है ताकि आगे से खाद की एजैंसिया भाहर वालों की बजाय गांव के लोगों की या एक्स मिलिट्ररी मैनज को ही दी जाएं।

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, यह बडा अच्छा सवाल है। मैं आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि यह विचाराधीन ही नहीं बल्कि हमने इस पर एक ान भी ले रखा है। हमने यह हिदायतें भी दे रखी हैं कि किसी प्राईवेट व्यक्ति को एजेन्सी न दी जाए। इसीलिये फर्टीलाईजर की जो डिस्ट्रीब्यू ान हो रही है, वह सरकार एजेन्सियों के थ्रू हो रही है और आगे के लिये अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को खाद की ऐजैंसी दी जाएगी तो वह किसानों को और देहातों में रहने वाले लोगों को ही दी जाएगी।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मैंने मिनिस्टर साहब को खाद के एक स्कैंडल के बारे में अवगत कराया था और इस बारे इंक्वायरी की रिकवैस्ट भी की थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर सैक्रेटरी की डयूटी भी लगाई थी कि वह रिपोर्ट पंजाब से मंगवाई जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्षः सुखदेव सिंह जी, आप मेने सवाल में ही संबंधित सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

चौधरी देस राजः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में कोई ऐसी बात है कि जहां से खाद इम्पोर्ट होती है, वहां पर उनके अपने कोई रिप्रेजन्टेटिव नहीं होते और इसी वजह से वजन कम निकलता है।

क्या सरकार ऐसा कोई प्रबन्ध करने का विचार रखती है कि उसी वक्त ही खाद को चैक कर लिया जाए ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्त को यह खबर कहां से मिली है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पर गवर्नमैंट आफ इंडिया के रिप्रेजन्टेटिव मौजूद होते हैं। और फिर उनके थ्रू रि बैगिंग करा कर, उस खाद को डिस्टैंट एरियाज तक पहुंचाया जाता है।

श्री कंवल सिहः स्पीकर साहब, अभ मन्त्री महोदय ने बताया कि खाद इकट्ठी होती है और दोबारा उसको रि बैगिंग करते हैं। रि बैगिंग करने के बाद क्या उस खाद को चैक किया जाता है कि उसका वजन ठीक है या नहीं ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ठीक है। जब रि बैगिंग करते हैं तो उसको तोल के हिसाब से ही करते हैं।

चौधरी ि िव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि हैफेड और मार्किट सोसायटीज के द्वारा किसानों को खाद दी जाती है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में है कि कई जगहौं पर किसानों की ि ाकायतें हैं कि खाद तोल कर नहीं दी जाती और जो खाद दी जाती है वह भी पत्थर जैसी होती है। क्या सरकार इस बात की इंक्वायरी करने का विचार रखती है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, हमारा एक सिस्टम है जिसके मुताबिक कोआपरेटिव सोसायटीज के थ्रू खाद दी जाती हे और जैसा चौधरी िाव राज जी ने कहा, उसके मुताल्लक मैं इतना ही कहना चाहताह ूं कि इसका इलाज तो हमारी बजाये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग हमें बताएं कि फलां जगह गलती है, उसको हम 24 घंटे के अंदर अंदर दरूस्त करेंगे।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर कोई खाद तुलवा कर लेना चाहे तो उसे खाद तोल कर दी जाती है। हैफेड और कोआपरेटिव सोसायटीज वाले टोटली बिना तोले ही देते हैं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई प्रबंध करने का विचार रखती है कि खाद को पहले ही तुलवा कर उठाया जाए ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, मेरे आनरेबल दोस्त ने एक नई सी बात कही है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब फैक्टरी से बैगज बनकर निकलते हैं तो लेने वाले को तो उसी वक्त पता लग सकता है कि इसमें अंदाजन कितनी खाद कम है। अगर खाद कम हो तो लेने वाले को यह चाहिए कि वह न लें यह तो एक सिम्पल सी बात है।

Share of water from Beas Project

***987. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the latest position of construciton of Sutlej Yamuna Link Canla in Punjab area; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to get the share of water from Beas Project through an alternative source till S.Y.L. Canal in Punjab territory is completed ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(क) पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना लिंक नहर पर निर्माण का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) हां, भाग के कुछ अं ा के लिये विकल्प साधन है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो बात डिसकस हो चुकी है और वजीर साहब ने अपनें जवाब के ख भाग में यह कहा भी है कि हां, भाग के कुछ अं ा के लिये विकल्प साधन हैं तो स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो हमारा भाग है, उसके अनुसार वहां से पानी क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिह: स्पीकर साहब, जितनी कपेसिटी अवेलेबल है, उतना पानी हम ले रहे हैं।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सै ान में जब से इधर बैठा करते थे तो बडे जो ा के साथ कहते थे कि

अगले महीने में ही काम भाुरू हो जाएगा और यह भी कहा था कि दोनों चीफ मिनिस्टर्ज वहां जाकर उदघाटन भी करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक वहां का काम भाुरू क्यों नहीं हुआ क्या पैसे की कमी के कारण या किसी दूसरे टकराव के कारण भाुरू नहीं हुआ है या इसके कोई और कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, यह मामला कई दफा पहले भी डिसकस हो चुका है और इस बारे में सारी बातें सदन के सामने आ चुकी है भाायद मेरे माननीय सदस्य उस समय सदन में नहीं थे या उनका ध्यान कहीं और था।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मन्त्री महोदय हाउस में कोई ए योरें ा दे सकते हैं कि इस काम को ज्यादा से ज्यादा इतने टाइम में भाुय करवा दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिहः जी नहीं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः जैसे मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि इम अपने भोयर का कुछपानी ले रहे हैं लेकिन चूंकि एस0वाई0एल0 का पानी अगले साल में आता नजर नहीं आ रहा है तो क्या बी0एम0एल0 के दोनों किनारों को रेंज करके या मजबूत करके और पानी लेने की कोि ा ा की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सिहः भाखडा मेन लाइन की केपेसिटी 12500 क्यूसिक्स की है और वह इन सालों में घटती बढती 11

हजार क्यूसिक्स के करीब रह गई है। माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि बी0एम0एल0 के दोनों किनारों को थोडा सा रेज करके पानी की कुछ मिकदार बढाई जा सकती है लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह मामला भी दोनो स्टेटस का आ जाता है। अभी तो पहले मामले में ही अडचन पडी हुई है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि कुछ पानी हम ले रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितना पानी लेना भाुरू किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः तकरीबन 8एम0ए0एफ0।

चौधरी पीर चन्दः जैसे कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बारे में अडचन पडी हुई है तो यह अडचन कब तक मिट जाएगी ?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है।

Pay Scales of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat Employees

***1041. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be pelased to state –

(a) whether the pay scales of the officers/officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat are at par witgh the officers/officials of the Civil Secretariat, Haryana; and

(b) if not, the steps taken or porposed to be taken to bring at par the pay scales of the employees of the Haryana Vidhan Sabha Secretriat with those of the Haryana Civil Secretariat ?

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) नहीं जी।

(बी) सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त कर दिया है। वेतनमानों में सं ाोधन करने के प्रस्ताव/सुझाव अब उस आयोग द्वारा विचारे जायेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगें कि जो पिछले बजट सै ान की कार्यवाही अभी तक प्रिंट नहीं हुई तो उसका कारण यही तो नहीं है कि विधान सभा के स्टाफ को कम तनखाह दी जाती है ? इसके अलावा क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक पे कमी ान की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक विधान सभा स्टाफ को सैक्रेटेरियट के बराबर तनखाह दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब दे दिया है और यह कनवैन ान भी है कि विधान सभा के बारे में ज्यादा सवाल न पूछे जाएं।

Water Supply works for Barwala

***971. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Local Governmnet be pleased to state –

(a) the capacity of the Barwala Water Supply Works for Barwala Town;

(b) whether the Government is aware of the fact that it is not adequate for the population of Barwala Town ; and

(c) if the reply of part (b) above is in the negative, the steps so far taken or proposed to be taken to improve the position ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) प्रतिदिन 50000 गैलन पानी

(बी) हां जी, पर्याप्त नहीं है

(सी) जल वितरण की बढ़ौतरी के लिये एक अनुमान तैयार किया जा रहा है।

श्री जगन नाथ: मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज से 15–20 साल पहले की जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं उनसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच गैलन पानी दिया जाता था लेकिन अब पहले से आबादी दूगनी हो गई है और पानी वही है तो क्या उस पानी को आबादी के हिसाब से बढाने की तजवीज हे ?

श्री वीरेन्द्र सिहः जहां पहली स्कीमों के तहत आबादी बढ गई है उन सब को आगमैंट किया जाएगा और पानी बढाया जाएगा।

श्री भाम ोर सिंहः क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह चीज है कि नरवाना टाउन की वाटर सप्लाई की स्कीम 15 दिन पहले सारी कलैप्स हो गई है और वहां की कमेटी ने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को उस स्कीम को टेक ओवर करने के लिये कहा है और खर्चा देने के लिये कमेटी तैयार है तो क्या इस पर कोई विचार किया गया है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिहः रिकवैस्ट आएगी तो कंसिडर की जाएगी।

श्री जय नारायण वर्माः क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बरवाला में मंडी के लिये जो वाटर सप्लाई है उसकी कैपेसिटी बढा कर उससे बरवाला नगर को भी पानी देने के लिये नीचे से कोई स्कीम आई है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः बरवाला में पहले ग्राम पंचायत होती थी और अब वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी है। कायदा यह है कि पानी बढाने के लिये एन0ए0सी0 को रिक्वैस्ट करनी पड़ती है लेकिन एन0ए0सी0 ने आज तक कोई रिक्वैस्ट नहीं की है। फिर भी सरकार अपनी ओर से एक 30 लाख रुपये की स्कीम बना रही है ताकि यह पानी बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जो सप्लीमैंटरी पूछैं वह मेन सवाल से सम्बंधित होनी चाहिए क्योंकि जो सप्लीमैंटरी सवाल से सम्बंधित नहीं है वह पूछना उचित नहीं होता है।

चौधरी लाल सिंहः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हर भाहर में म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा या नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा घरों मैं पानी का कनैक ान दिया जाता है तो गांवों में क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री वीरेन्द्र सिहः गांवों में कनैक ान इसलिये नहीं दिये जा रहे कि वहां पर सीवरेज सिस्टम नहीं है और पानी के लगातार चलने से वहां पर कीचड हो जाता है जो कि लोगों की सेहत के प्वायंट आफ व्यू से ठीक नहीं है। इसलिये जब तक स्टेट के पास गांवों में सीवरेज सिस्टम चलाने के लिये पैसे का प्रबन्ध नहीं होता तब तक गांवों में कनैक ान नहीं दिये जाएंगे।

कामरेड भांकर लालः सिरसा भाहर के अन्दर जब 35–40 हजार की आबादी थी तो उस समय वहां पर एक वाटर वर्कस बना था। अब उस भाहर की आबादी दुगनी हो गई है। क्या वहां पर कोई दूसरा वाटर वर्कस बनाया जाएगा या और तरीके से पानी बढ़ाया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिहः माननीय सदस्य कहते हैं कि सिरसा में ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन इस सै ान से इन्होंने सिरसा के

लिये मांग भाुरू की है जैसे कि आज वहां के लिये इन्होंने पानी की मांग की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर वाकई पानी की कमी है तो उस पर गौर किया जाएगा।

Amount for Sowing, Plantation if Forest Department

***996. Dr. Brij Mohan Gupta :** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) the total amount provided to Forest Department for various purposes (sowing, plantation, construction of roads and other miscellaneous works) during the financial year 1977-78;

(b) the total amount out of that referred to in part(a) above that has been spent on wages; and

(c) the amount spent on the purchase of materials ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

		रुपये
(क)	(1) बुआई तथा पौधारोपण (2) सड़कों तथा रास्तों का निर्माण	15360248 156928

	(3) अन्य फुटकर कार्य	2317200
	जोड़ (क)	**17834376**
(ख)		14130860
(ग)		1386370

डा0 बृज मोहन गुप्ताः मन्त्री जी ने बताया कि फारैस्ट का कुल बजट 17834376 रुपये है और उसमें से 1977–78 में 15517230 रुपये खच हुआ और करीब 23 लाख रुपये लैप्स हो गया यानी खर्च नहीं हो सका। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो 23 लाख रुपया लैप्स हो गया वह किन अफसरों की वजह से और किन कारणों से हुआ ?

श्री अध्यक्षः यह कहीं नहीं बताया गया है कि इतना पैसा लैप्स हो गया है। डा0 साहब आप जवाब को अच्छी तरह से स्टडी करें।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फारैस्ट वालों को ऐसी हिदायतें देने जा रहे हैं कि सडकों पर फलदार वृक्ष ज्यादा लगाये जाएं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, फलदार पौधे सडकों पर लगाने बहुत मु कल होते हैं क्योंकि इनकी रखवाली करनी मु कल है। अलबत्ता पहले जहां हम कीकर के दरख्त लगाते थे उनकी बजाये हमने भी ाम और सफेदा वगैरह के दरखत लगाने की कोि ा ा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यू0पी0 में मैंने देखा है कि आम के पेड़ आम सड़कों पर लगे हुए हैं। उनकी चौकीदारी की कोई जरूरत नहीं पडती बल्कि उनको देहाती भाई खाते हैं और उनकी भूगर की कमी भी दूर होती है। (हंसी)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप का पेड हर जगह नहीं लग सकता।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब बांध बांधे गये थे तो सबसे ज्यादा मेरे हल्के में कीकर के पौधे रोपे गये थे जो अभी छोटे हैं। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी जगह भी ाम वगैरह और फलदार पौधे लगाये जाएंगे ?

चौधरी भजन लालः कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ऐसे पौधे बिल्कुल नहीं लग पाते हैं। अब फैसला किया गया है कि कीकर की बजाये भी ाम, सीरस फलदार तथा सफेदे के पौधे लगाये जायें जैसे अम्बाला जिला में आम के पौधे लग सकते हैं।

हमारी कोि ा ा यही होगी कि जहां फलदार पौधे लग सकते हैं वहां हम फलदार पौधे अव य ही लगाने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारे गुडगांव जिले का काफी क्षेत्र पहाडी है और जमना भी हमारे जिले के क्षेत्र से निकल कर जाती है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस खादर के क्षेत्र में और जहां पहाडी इलाका है वहां पर कोई खास प्लांटे ान की योजना विचाराधीन है ?

चौधरी भजन लालः पहाडी इलाके में ज्यादा से ज्यादा जंगलात लगाने की कोि ा ा करते हैं और लगाते हैं और इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं जैसे महेन्द्रगढ, भिवानी, सिरसा और हिसार जो कि हरियाणा के बार्डर पर हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोि ा ा की जा रही है ताकि राजस्थान की आरे से रेत जयादा न आए और रेगिस्तन को रोका जाए।

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, जिन दरखतों को लगाने की बात मन्त्री जी ने बतायी है उनके कामयाब होने की बहुत कम सम्भावना है। क्या इन दरखतों के नाकामयाब होने की परसैंटेज को कम करने की कोि ा ा की गई है ?

चौधरी भजन लालः जितने पौधे लगाये जाते हैं हो सकता है उन सब की पूरी देखभाल न हो सकी और 15–20 परसैंट पौधों को लगाने में कामयाबी न मिली हो, लेकिन 80 प्रति ात पौधों में तो कामयाबी हुई है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, कुछ पंचायतों ने 10–20–30 एकड पंचायती जमीन फोरेस्ट डिपार्टमैंट को दे दी है परन्तु उस जमीन में फोरैस्ट डिपार्टमैंट की ओर से आज तक कुछ भी नहीं लगाया गया है, वाहं झाडियां अपने आप उग जाती हैं क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वहां पर कुछ पौधे लगाने का विचार है ?

चौधरी भजन लाल: जो पंचायतें हमें जमीन देती हैं उनमें हर दरखत लगाते हैं जंगलात महकमा उस सारे क्षेत्र में दरखत लगाता है फिर उस क्षेत्र को पांच साल तक बंद रखा जाता हैं जब पेड कामयाब हो जाते हैं तो हम उन्हें पंचायतों को फ्री दे देते हैं उनसे कोई पेसा चार्ज नहीं किया जाता।

चौधरी ि◌ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो कीकर लगाई जाती हैं वे देसी होनी चाहिए लेकिन पहले जो लगाई गई हैं वे पहाडी कीकर हैं जो बेकार हैं। स्पीकर साहब, पहले सरकार की एक स्कीम थी कि जो किसान अपने एक या चार किल्ले जमीन जंगलात महकमें को प्लांट लगाने को दे देता था वह जमीन प्लांट कम्पलीट होने पर फिर उसे वापिस दे दी जाती थी क्या इस स्कीम को दोबारा चलाने का कोई विचार है ?

चौधरी भजन लाल: यह स्कीम अभी भी लागू है। वैसे तो काई भी किसान अपनी जमीन जंगलात महकमे को पोधे लगाने को नहीं देता है परन्तु इसके बावजूद भी जंगलता महकमा पूरी

कोि ा ा करता है कि अधिक से अधिक पोधे लगाए जाएं। अगर कोई किसान अपनी जमीन में पौधे लगवाना चाहता है तो उससे फ्री पौधा 25 पैसे लिये जाते हैं पिछले साल इस तरह जंगलात महकमे ने 80 लाख पौधे लगाये थे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, ये जो पोधे लगाये गये हैं इन पर फारैस्ट के गार्ड को इतनी पावर दे रखी है कि अगर कोई बच्चा भी कोई पेड खराब कर देता है तो उससे दो सौ रुपया तक जुर्माना लिया जाता है क्या उस गार्ड की पावर्ज को कम करने का कोई विचार है ?

चौधरी भजन लालः गार्ड अगर कायदे से बाहर जाकर किसी के साथ ज्यादती करता है तो हम उसका जरूर इलाज करेंगें, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे।

चौधरी लाल सिंहः जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया है कि अम्बाला जिले में आम के पेड लग सकते हैं क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अम्बाला जिले की किन तहसीलों और कांस्टीच्यूएंसीज में ये फलदार पौधे लगवा रहे हैं ?

(इस प्रगन का उत्तर नहीं दिया गया।)

डा0 बृज मोहन गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वै चन तो यह था कि 1977–78 में जो बजट अलाट किया गया था वह 1 करोड 78 लाख का था उसमें से 1 करोड 55 लाख रुपये खर्च हुए और 23 लाख रुपये बच गये जो लैप्स हो गये। मैं जानना

चाहता हूं कि इन पैसों के लैप्स होने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

चौधरी भजन लालः जो माननीय सदस्य ने सवाल किया था उसका जवाब दे दिया गया है लेकिन उन्होंने समझने की कोि ा ा नहीं की। लैप्स होने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने बताया है कि टोटल पैसा इतना दिया।

श्री अध्यक्षः पैसा बचने का तो सवा पैदा नहीं हेात। यह जो 23 लाख रुपया है यह अदर मिसलेनियस वर्क्स के लिए दिया गया था और उसके बचने की तो बात ही नहीं है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा था कि कितना टोटल अमांउट प्रोवाइड किया गया था और उसमें से कितना अमांउट वेजिज तथा मैटीरियल परचेज करने पर खर्च किया गया। मैंने बताया है कि टोटल 1 करोड 78 लाख 34 हजार 376 रुपया प्रोवाइड किया गयो जिसमें से 1 करोड 41 लाख 30 हजार 860 रुपये वेजिज पर खर्च हुए तथा 13 लाख 86 हजार 370 रुपये मैटीरियल खरीदने पर खर्च हुए। बाकी जो 23 लाख 17 हजार 200 रुपये हैं, ये बचे नहीं हैं, ये तो अन्य मिसलेनियस कामों में खर्च किये गये हैं।

Production of wheat in the State

***1057. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be please to state the total production of wheat during the Rabi harvest of 1978 in Haryana ?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): हरियाणा राज्य में रबी 1978 (भाव वश्र 1977–78) में गेहूं का कुल उत्पादन 28.71 लाख टन हुआ है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वर्श 1978 में सरकार ने कितनी गेहूं खरीदी और किस भाव से खरीदी ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: यह सवाल तो प्रोडक ान के बारे में किया गया था खरीद के बारे में नहीं था।

श्री अध्यक्ष: अगर अलग नोटिस देंगे तो उसका जवाब मिल सकताहै।

श्री भाम ोर सिंह: पिछले साल हरियाणा में किस भाव से गेहूं की खरीद हुई और इस साल सरकार ने किस भाव की मांग की है ?

ब्रिगेडियर रण सिंह: यह सवाल मुख्तलिफ है। फिर भी मैं बता दूं कि व्हीट की कास्ट प्रोडक ान की जांच पडताल हमने की है, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जिस कीमत की मांग की गई है, अगर वह मिल जाये तो ठीक है।

श्री जगन नाथः यह जो 28.71 लाख टन के आंकडे दिये गये हैं ये आंकडे किस प्रकार से इकट्ठे किय गये हैं क्या हरेक खेत में गेहूं तोल कर इकट्ठे किये गये हैं ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः यह आंकडे स्टेटिस्टिकल विभाग द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं पांच परसैंट इधर से उधचर भी हो सकते हैं लेकिन यह कहना कि खेत में तोल कर इकट्ठे किये गये हैं, यह ठीक नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मैं वजीर साहब से पूछना चाहूंगाकि क्या किसान को गेहूं का भाव 150 रुपये क्विंटल देने का विचार है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः यह सवाल भाव का नहीं है।

चौधरी ई वर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि किस जिले में सबसे ज्यादा पैदावार होती है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुये बडी भारी खु ाी है कि कुरुक्षेत्र जिले 2475 किलोग्राम तक की पैदावार एक हैक्टेयर में होती है और दूसरे नम्बर पर हिसार जिला है जहां पर 2221 किलोग्राम तक प्रति हैक्टेयर पैदावारी होती है।

श्री देवेन्द्र भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिला जो आपको इतना रैवेन्यू देता

है उसको इग्नोर करके आपने यतीमों का जिला क्यों बना रखा है ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

Construction of Canals

***914. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the constituency wise number of new canals constructed and tails of old canals extended during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the State; and

(b) the constituency wise number of newly constructed distributories and the name of the canals from where these have been taken out during the periodc as referred to in part (a) above ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(ए) 4 जुलाई 1977 से 30 जून 1978 तक राज्य में जितनी नई नई नहरों का निर्माण किया गया और पुरानी नहरों के टेलों को आगें बढाया गया, उसका विवरण विधान सभा क्षेत्र अनुसार अनुबंध ए सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(बी) 4 जुलाई 1977 से 30जून 1978 तक जितनी नई डिस्ट्रीक्यूटरियां बनाई गई और जिन नहरों से यह निकाली गई हैं

उनका विवरण विधान सभा क्षेत्र अनुसार अनुबन्ध बी सदन के पटल पर रख दिया है

अनुबन्ध –ए

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	नई नहरें जिनका निर्माण किया गया	जितनी पुरानी नहरें जिनकी टेलें आगे बढाई गई
1	नागल	4	
2	भााहबाद	1	
3	पेहवाव	1	
4	थानेसर	1	
5	नीलोखेडी	1	
6	करनाल	1	
7	जाटुसाना	6	
8	रिवाडी	9	
9	बावल	12	
10	कनीनी	7	

11	बथेडा	7	1
12	बवानी खेडा		1
13	लोहारू	11	1
14	तो ाम	5	
15	दादरी	3	
16	महेन्द्रगढ	8	
17	बेरी	3	
18	कलानौर	1	
19	बरवाला	1	
20	राजौंद		1
21	रोहट		1
22	कइलाना		1

अनुबन्ध –बी

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र	डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम	नहर का नाम जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटरी

			निकाली गई
1	नागल	कनवाला	सतलुज यमुना लिंक नहर
2	जाटुसाना	दिवाना डिस्ट्री सिस्टम और उनकी अन्य भााखाएं (क) मुसापुर (ख) बालावास (ग) रसोली रामपुरी	जवाहर लाल नेहरू नहर महिन्द्रगढ नहर
3	रिवाड़ी	भााखाएं जो दिवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से निकाली गई (क) बालवास (ख) रसोली	

		भोखपुरा निकरी जीतपुर जाटुवास कमालपुर रालीयावास रतनपुर	जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर जवाहर लाल नेहरू नहर
4	बावल	कमलपुर	जवाहर लाल नेहरू नहर
		रतनपुर	जवाहर लाल नेहरू

			नहर
		राजीका	जवाहर लाल नेहरू नहर
		अकबरपुर	जवाहर लाल नेहरू नहर
		बोलनी	जवाहर लाल नेहरू नहर
		खेडी गोटाला	जवाहर लाल नेहरू नहर
		बावल	जवाहर लाल नेहरू नहर
		जलालपुर	जवाहर लाल नेहरू नहर
		मंगले ावर	जवाहर लाल नेहरू नहर
		बि ानपुर बि ानोर	जवाहर लाल नेहरू नहर
		मंजारपुर	जवाहर लाल नेहरू

			नहर
5	कनीना	भााखाएं जो विडावास डिस्ट्रीब्यूटरी से निकाली गई	
		बलोर	महिन्द्रगढ़ नहर
		बसी	महिन्द्रगढ़ नहर
		रामगढ़	महिन्द्रगढ़ नहर
		आलट	महिन्द्रगढ़ नहर
6	बडैहरा	बलोर	महिन्द्रगढ़ नहर
7	तो ाम	साराल	निगाना नहर
8	महिन्दगढ़	नारनौल ब्रांच	महिन्द्रगढ़ नहर
		खेड़ी	महिन्द्रगढ़ नहर
		बवाना	महिन्द्रगढ़ नहर
		लान	महिन्द्रगढ़ नहर
		महिन्द्रगढ़	महिन्द्रगढ़ नहर

		पथेड़ा	नारनौल ब्रांच
		जोख	नारनौल ब्रांच
		नागल	नारनौल ब्रांच
9	बेरी	दिवसा डिस्ट्रीब्यूटरी	जवाहर लाल नेहरू नहर

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर को दृश्टिगत रखते हुए यह जानना चाहूंगा कि सारे हरियाणा राज्य में 19 महीनों के अन्तर्गत 19 हलकों में महेन्द्रगढ़ से ले करके रोहतक तक 82 नई नहरें बनाई गई हैं और इन हल्को में पुरानी नहरों की टेल को भी आगे बढ़ाया गया है लेकिन जो बाकी जिलें हैं उनमें नई नहरों का निर्माण क्यों नहीं हुआ और उनकी टेल को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

श्री वीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी तो थ्योरैटिकल क्वै चन पूछ रहें हैं यह तो पानी दैने का सवाल हैं जहां पर पानी की अधिक आव यकता होती है वहीं पर ही टेल को आगे बढाया जाता है और जहां पर नहर की आव यकता होती है वहीं पर नई नहर की खुदाई की जाती है।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या गुडगांव जिले में पानी की मांग नहीं है

और क्या गुडगांव जिले की नहर को आगे बढाने की आव यकता नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, स्वामी जी यह सवाल जिस इनटैंन ान से पूछा था वह दरअसल इनकी पूरी नहीं हुई। न हिसार जिले में किसी नहर की बढौतरी हुई है और न ही सिरसा जिले में हुई है। अब यह दायें बायें के सवाल पूछ रहे हैं ? गुडगांव जिले में पानी की बहुत आव यकता है और सरकार जो कुछ प्रबन्ध कर सकती है वह कर रही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुलयाना गांव जो कि चौधरी साहब के गोत का है, वहां पर तकरीबन एक साल पहले एक नहर मंजूर की गई थी परन्तु उस नहर की खुदाई का काम अभी तक भाुरू नहीं हुआ है तो उसकी खुदाई कब तक भाुरू करवा देंगे ?

श्री अध्यक्षः चौधरी जगजीत सिंह पोहलू, जी पानी और गोत का क्या सम्बंध है ?

श्री जय नारायण वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छान माईनर को आगे क्यों नहीं बढाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, उसका स्टे आर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। इसलिये नहीं बढायी गई।

चौधरी गया लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जब कि मंत्री महोदय मान चुके हैं कि गुडगांव जिले में पानी की काफी जरूरत है तो फिर किस तरीके से वहां के लोगों को पानी देने का प्रबंध कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, पानी नहर से दिया जाएगा।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि नई नहरों की खुदाई वहां होती है जहां पानी की जरूरत हों क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि गोरड माइनर तथा कुछ और माइनर्ज के प्राजैक्टस नीचे से बन कर सैक्रेटेरिएट लैवर पर मंजूर होनै के लिए गए हैं और दो तीन साल से सैक्रेटेरिएट में कागज पडे हुए हैं। क्या उन पर सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी लैवल से मंजूरी होने के बाद तो फाईल सीधी मेरे पास आती है। दो तीन साल की फिगर्ज चौधरी साहब पता नहीं कहां से ले आए ? हम तो 18 महीने से यहां हैं ज्यों ही फाईल आ जाएगी मंजूर कर देंगे।

चौधरी गंगा रामः अध्यक्ष महोदय, मेरें हल्के में 5–6 गांव ऐसे हैं जिनके आधे खेतों में बिल्कुल पानी नहीं लगता। मैं एक रजवाहे को एक्सटैंड करवाने के लिए एक डेढ साल से एक

एक फाईल को लिए फिर रहा हूं और मुख्य मंत्री महोदय भी एक दो दफा कह चुके हैं और उन गांवों के आदमियों ने बिल्कुल एक मत होकर एस0ई0 और एक्स0ई0एन0 के सामने यह कहा कि यह रजबाहा बन जाना चाहिए लेकिन अब तक वह फाईल मंत्री महोदय तक नहीं पहुंची है। मैं हार करके बैठ गया हूं। क्या मंत्री महोदय मेरे ऊपर दया करके उस रजबाहे को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी इतनी जल्दी हिम्मत न हारें आप उस फाईल को एक दफा और लेकर आएं।

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिले के गांवों की धरती से जो जहर निकाली गई है वहां के लोगों को उस नहर का पानी भी नहीं दिया गया है और वहां पर पानी रिस रिस करके सेम बढती जा रही है। क्या इस पर का कोई विचार किया जाएगा ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नाहरी माइनर और गोरड माइनर की स्कीमें आपके मंत्री बनने से पहले से मंजूर हो चुकी थी लेकिन उन पर अभी तक काम चालू नहीं हो सका। इसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, मैं वह फाईल निकलवा कर देखूंगा।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, मैं एक ए योरेंस चाहूंगा कि वजीर साहब .....

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूलिछए यह ए ायोरैंस का टाईम नहीं है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां पानी की बहुत जरूरत है, वहां पानी की सतह नीचे है इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब और वजीर साहब से भी यह दरख्वास्त है कि नहरें बनाई जाएं ताकि लोगों को दिक्कतों को दूर किया जाये।

श्री अध्यक्ष: आप तो सुझाव दे रहे हैं, आप सवाल पूछिए।

श्री गुलजार सिंह: अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट जींद के राजौंद हलके में भी कोई माइनर एक्सटैंड नहीं हुई और अभी हाल ही में जब मुख्य मंत्री महोदय वहां गए तो उनसे भी रिक्वैस्ट की थी। क्या मंत्री महोदय उस हल्के में भी किसी माइनर को एक्सटैंड करने के बारे में सोचेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिह: स्पीकर साहब, उस हल्के में माइनर्ज को एक्सटैंउ करने के लिए टैक्नीकल एक्सपर्टस ने इंकार कर दिया है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Dalmia Dadri Cement Factory Charkhi Dadri

***1030. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Develoment be pleased to state-

(a) the arears of Pay; Bonus, Gratuity as also the amount of arrears still dut ot ht workers as a result of arbitration award dated 26-9-78 from the management of Dalmia Dadri Cement Factory, Charkhi Dadri;

(b) whether the management of the said Factory has given the notice of the closure of the factory; if so, the steps proposed to be taken by the Government to prevent the closure thereof;

(c) whether it is a fact that late Seth Ram Krishan Dalmia had with drawn Rs. 2 crore and 20 lacs out of the funds of the said Company which was to be repaid by him from March, 1974 onward; and

(d) whether it is a fact that the amount mentioned in part (c) above has not been repaid so far, if so, the action proposed to be taken by the Government in this regard ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) 4 लाख से कुछ अधिक की राि ।

(बी) जी हां। फैक्टरी बंद नहीं हुई और अभी भी पहले की तरह चालू है। इस फैक्टरी के बंद होने के लिए सरकार कई कदम उठायेगी।

(सी) हां। 2 करोड 14 लाख रुपये की राि । ले रखी है।

(डी) हां। यह एक लिमिटिड कम्पनी है और इस पर कार्यवाही कम्पनी के भोयर होल्डर्ज ने करनी है।

Flow of water Barwali and Kutaian Minor

***895. Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Irrigation & Power be please to state-

(a) the quantum of water authorised to flow through Sharawali, Barwali and Kutiana Minor in Sirsa district; and

(b) whether the authorised water flows in full in the distributories as referred to in part (a) above; if not, the reasons therefor ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) Sherawli 183-5 Cs.

Barwali 193Cs.

Kutiana 90Cs.

(b) Bhakra water being silt free aloows penetration of sun rays throught it which induces weed growth causing reduction in capacity of channels. Sherwali, Barwali and Kutiana Distrys. can be fed with the authorised full supply discharge only when these are cleared of weed growth alongwith the weed clearance of Fatehabad Branch. Weed clearance is required once a month to ensure full supply.

Declaration of Surplus Coal

***988. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) whether it is a fact that coal was declared surples in Hissar Distrcit during the years 1976-77 and 1977-78, if so, the total quantity thereof togetherwith its value;

(b) the manner in which it was disposed of and the rate at which it was sold;

(c) whether it is a fact that market price of coald was much higher than the price fixed by the Government for its disposal to the private brikc kiln owners; and

(d) whther any responsibility was fixed for the loss thus suffered as a result of the slae of said coal to the private brick kiln owners ?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागरः

(ए) 4231.4 टन सलैक कोल जिसका मूल्य 358625.97 रुपये था खुली मार्किट में बेचने की अनुमति दी गई, क्योंकि इसकी भट्टे वालों की तुरंत आव यकता नहीं थी।

(बी) यह कोयला डैम्प करने के बाद संबंधित कोल एजैंटों द्वारा भट्टे वालों को 82.08 रुपये से 90.40 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा गया।

(सी) नहीं।

(डी) इसमें सरकार की निधि निहित नहीं थी इसलिये हानि की जिम्मेवारी नियम करने का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Qualificaiton for members of the Haryana State Electricty Board

***980. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the qualification, if any, presecribed or criteria fixed for the members (non technical) who are appointed as members of the Haryana State Electricity Board; and

(b) the total number of Members (non technical) who have been appointed in the Harayna State Electricity Board by the Janata Government till 31-1-1979, alongwith their qualifications and permanent address, separately ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(ए) केवल तीन मैम्बरों के लिये योग्यता निर्धारित की गई है। तकनीकी मैम्बर के अतिरिक्त दो गैर तकनीकी के लिये निर्धारित योग्यता इस प्रकार है :–

1. एक व्यक्ति वह होगा जिसे प्र ाासन तथा वाणिज्य कार्यों का अनुाव हो तथा इन कार्यों के करने में क्षमता दिखाई हो।

2. एक व्यक्ति वह होगा जिसे लेखा तथा वित्तीय मामलों में किसी सार्वजनिक उपयोग संस्था का अनुभव हो, किसी बिजली सप्लाई संस्था में ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी।

3. जनता सरकार ने 31 जनवरी 1979 तक 6 व्यक्ति गैर तकनीकी मैम्बर लगाये हैं। उनकी योग्यता तथा स्थाई पता नीचे दिया गया है :–

नाम तथा पता		योग्यता
1	श्री एच0वी0 गोस्वामी, आई0ए0एस0 (हरियाणा सरकार)	आई0ए0एस0
2	श्री वी0पी0 जौहर, आई0ए0एस0 (हरियाणा काडर)	आई0ए0एस0
3	श्री जिया लाल जैन,	चारटर्ड अकाउटैंट, मुख्य

	9—मोडल बस्ती, नई दिल्ली— 5	लेखा के रूप में विभागाध्यक्ष। इससे पहले बतौर वित्तीय तथा लेखा मैम्बर दो साल तक कार्य किया, बिजली बोर्ड में आने से पहले चारटर्ड अकाउटैंट के रूप में कई कम्पनियों तथा फर्मों में जिन में बिजली की कम्पनी भी भाामिल है, काम किया।
4	श्री कु ाल पाल सिंह, गांव बारवाला (रोहनाडियार) तहसील कैथल जिला कुरुक्षेत्र	इंटरमिडिएट
5	श्री उदा राम, वकील, बरनाला रोड, सिरसा	बी0ए0 एल0एल0बी0 20 वर्श से वकील
6	श्री राम सिंह, गावं तथा डा0 वजीरपुर, जिला गुड़गांव	बी0ए0

Shortage of accomodation in Gorvernment High School, Barwala

***972. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the accommodation in Govt. High School, Barwala is not adequate;and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet the shortage of accommodation in the said school ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) जी हां।

(ख) सरकारी भवन के अतिरिक्त प्राथमिक कक्षाओं के बैठाने के लिए एक अन्य अराजकीय भवन किराये पर लिया गया था। बाद में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सात अन्य कमरे और एक विज्ञान प्रयोग ाला का भी प्रबन्ध हेतु आगे प्रयास जारी है।

Amount for the construction of roads, bridges and buildings in the State

***994. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) the total amount of budget allotted for the construction of roads, bridges and buildings during the financial year 1977-78;

(b) the total amount out of that referred to in part (a) above which has been actually spent for the purpose for which it was allotted during the year 1977-78; and

(c) the total amount spent for the purchase of builing materials during the financial year 1977-78 ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) 2312.55 लाख रुपये।

(बी) 2322.25 लाख रुपये।

(सी) 138.45 लाख रुपये।

Ban on Export of Cattle

***1099. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governmnet to impose ban on the export of cattle from Haryana;

(b) if so, the time by which the said decision is likely to be taken. and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government to achieve white revolution by ensuring the stoppage of export of milch cattlel from the State and by opening 'Goasadans, if so, the steps so far taken or porposed to be taken in this behalf ?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं जी।

(ख) उपरोक्त (क) के दृश्टिगत प्र न ही नहीं उठता।

(ग) दुधारू प ुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने या गोसदन खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

T.A. Drawn by the Chief Minister

***1082. Rao Ram Narain;** Will the Chief Minister be please to stater the expenditure incurred by the State Government when the Chied Minister used aeroplane for his tours since he assumed office ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): राज्य सरकार की और से मुख्य मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के समस ये 31 जनवरी 1979 तक सहकारी जहाज में यात्रा पर 18642527 रुपये की रा ि ा खर्च की गई।

Widow Homes

***1066. Captain Mange Ram;** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state-

(a) whether there are any Government oreders to the effect that only female Superintendents be posted in Widow Homes being run under the Social Welfare Department; and

(b) if reply to part(a) above in the affirmative, whether there are any such widow homes in the State where male Superintendents have been posted; if so, the reasons therefor ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) जी हां।

(ख) हरियाणा राज्य में तीन विडो होम्ज, करनाल, रोहतक और फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं जहां पर सभी अधीक्षक महिलाएं ही लगी हुई हैं।

Drining Water Scheme in Kalanuar Constituency

***1012. Shri Jai Narain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether theree is any scheme under consideration of the Govenment to provide drinking water to the village in Kalanaur Assembly Constituency of district Rohtak, if so, the details thereof ?

लोकनिर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): जी हां। कलानौर चुनाव क्षेत्र के चार गांवों के लिये तीन योजनाएं काहनौर, खैरडी तथा समरगोलपुर समूह पर कार्य हो रहा है। तीन और गांव पिलाना, खरक कलां तथा खरक खुर्द की जल वितरण योजना का राज्य सैनिटरी बोर्ड द्वारा प्र ाासकीय अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Change in pattern of Education in the State

260. Master Shiv Parshad: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether the Education Department has considered any proposal for bringing any change in the present pattern of Education in the State after formation of Janata Government; if so, the nature thereof; and

(b) if not, whether the Education Department is formulating any scheme by which students will get facilities for getting jobs after completing their education ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) हां, भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ने नई ि ाक्षा प्रणाली 10+2+3 को क्रमवार लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को तकनीकी, व्यावसायिक ज्ञान तथा कार्यकु ालता देगीख जिससे उन्हें रोजगार मिलने में सुविधा रहेगी।

(बी) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Taking over of Private Colleges

261. Master Shiv Parshad: Will the Minister for Eduation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the private Colleges in the State which are running in loss; and

(b) if so, the names thereof togetherwith the time by which those are likely to be taken over ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य:

(ए) हां। सरकार ने अराजकीय महाविद्यालयों की स्थिति का परीक्षण करने के लिये एक सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया था और उसने इस संबंधमें कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं प्रत्येक कालेज की स्थिति पर गुण अवगुण के अनुसार विचार किया जा रहा है।

(बी) इस समय नामों का निर्दे ा करना संभव नहीं और न ही कोई अवधि दी जा सकती है।

Adhoc and Stipendiary Teachers

262. Master Shiv Parshad: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of teachers on ad hoc and stipendiary basis respectively in the State on the date when the Janata Govt. was formed; and

(b) whether there is any proposal under considaration of the Government for regularising the services of the said teachers if so, the time by which it is likely to be implemented ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) (1) स्टाइपैंडरी – 11170

(2) तदर्थ – 3397

(ख) सभी स्टाईपैण्डरी टीचर्ज मास्टर्ज/मिस्ट्रेसिज की सेवायें, जो निर्धारित योजनाओं की भार्त पूर्ण करते थे, दिनांक 1–1–1979 से नियमित की जा चुकी हैं। भोश स्टाईपेण्डरी मास्टर्ज/मिस्ट्रेसिज एवं उन मास्टर्ज/मिस्ट्रेसिज की सेवायें नियमित करने का मामला, जिनकी नियुक्ति अधीन सेवायें प्रवरण मण्डल के माध्यम से हुई और वे भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदो के विरूद्ध तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, सरकार के विचाराधीन है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये टीचर्ज/मास्टर्ज/सक्वैंड टीचर्ज की सेवाओं को नियमित करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Opening of Subsidiary Centres and Dispensaries in the villages

263. Master Shiv Parshad: Will the Minister for Health be please to state the names of the villages where subsidiary cerntres and dispensaries have been opened during the current financial year together with the names of the places wheree the centres are proposed to be opened during the next financial year ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा0 कमला वर्मा):

(क) चालू वित्तीय वर्श में निम्नलिखित प्र नों में सबसीडियरी हैल्थ सैन्टर स्थापित किये गये हैं :–

1. जहाजगढ़, जिला रोहतक।

2. जलमाना, जिला करनाल।

3. मांडी, जिला करनाल।

4. पुट्ठी मंगलखान, जिला हिसार।

5. पाबड़ा जिला हिसार (ग्रामीण डिसपैंसरी से परिवर्तित किया गया।)

चालू वित्त वर्श में कोई डिसपैंसरी नहीं खोली गई।

(ख) उन ग्रामों जिनमें अगले वित्त वर्श में सबसीडियरी हैल्थ सैंटर खोले जाने हैं के नामों का चयन अभी किया जाना है।

City-Corporations in the State

252. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of teh Government to set up city corporations in the State; and

(b) if so, the names of the cities where the city-corporatioons are likely to be set up together with the criteria being fixed there for ?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा):

(क) हां।

(ख) मामला विचाराधीन है और इस समय अपनाये जाने वाले आधार के बारे स्पश्ट रूप से कहना सम्भव नहीं है।

Water Sewarage Board in the State

253. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister for Local Government be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Water Sewerage Board in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to tbe materialized ?

स्थानीय भाासन मंत्री (राम लाल वधवा):

(क) हां।

(ख) निर्धारित समय बताया जाना सम्भव नहीं।

Rural Industrilisation

254. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the steps, if any, taken or propsed to be taken to promote Rural Industrialisation in the State; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up units under Rural Industrialisation Programme during the next financial year 1979-80 ?

Industries Minister (Dr. Mangal Singh):

(a) Rural Industries Scheme was launched in October, 1977 with a view to promoting Rural Industriallation in the State through the setting up of tiny units with capital investment not exceeding Rs. 1 lac by unemployed rural enterpreneurs belonging to wekaer sections of society and having no commercial interest in the cities. Under the scheme which is being implemented by the Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., w.e.f. September, 1978 following type of assistance is avilable :-

(i) Field Staff of the Industries Department and Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., are motivating and encouraging unemployed rural people to set up tine industries in the villages.,

(ii) Industries having scope for development in different areas have been identified and entrepreneurs are being encouraged to set up tiny units (with capital investment upto Rs. 1 lac) in clusters to facilitate provisition of raw material, common facility and marketing facilities through the establishjment or Rural Industries Promotion Centres in various Districts.

(iii) The interested entrepreneurs are assisted in the selection of the line of manufacture and are provided with the Project Profile free of cost.

(iv) Training to entrepreneurs wherever necessary is arranged through SISI, Nes Delhi and integrated Training Centre, Nilokheri.

(v) Assistance is provided for securing loans for the entrepreneurs from the Financial Institutions or State Government. Financial Assistance upto 80% of the Capital cost (including 3 months capital) by the Banking Institution or Haryana Financial Corporation is provided under this shceme. The State Government also provides 10% seed money/marging money to such units at the rate of 4% per annum which is repayable in easy instalments after the maini loan has been paid off. Further the State Government subsidies the rate of interest of Financial Institutions. These units are also provided capital subsidy as 15% on capital investment.

(vi) Raw material is provided to them proportionate to their assessed capacities/requirements. RIS units are given 100% additional allotement viz-a-viz other units.

(vii) Marketing assistance is provided where ever the units ask for it. Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd., is an approved source of supply for purchases by Government Departments. The Marketing Wing of the Corporation is making vigorous efforts to facilitate selling of products manufactured by RIS units. 10 to 15% price preference is given to the products manufactured by the units set up under Rural Industries Scheme.

(viii) Rural Artisans/entrepreneurs are encouraged to set up Cottage industries in clusters in collaboration with SFDA/CADA/DPAP agencies through a package of incetives including stipendiary training finacial assistance, raw material, supply of improved tools and machinery, marketing etc.

(ix) Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., is displaying the products of RIS units in exhibitions/fairs, thereby creating new avenues for marketing their products.

(x) Numerous additional incentives have been offered to the rural entrepreneurs to promote industrialisation in the rural areas namely;

(a) exemptaion from payment of stamp duty & registration charges required in the finalisation of equitable mortgages;

(b) exemption from electricity duty for a period of 7 years;

(c) exemption form sales tax & purchase tax for a period of 2 years on raw material, procession/packing material, machinery and finished goods;

(d) exemption from octroi on raw material for a period of 5 years to units in backward areas & rural areas, 10 K.M. beyong the Municipal Limits and tiny units in rural area; and

(e) interest free loan in lieu of central sales tax in rural areas for a period of 7 years.

(x) Rural Industries Promotion Centres are being established where entrepreneurs would be provided training, raw material assistance, common service facilities and marketing assistance etc.

(xii) Sales Depots are proposed to be set up at all the District Headquarters and other important towns of the State to facilitate sale of the products of the RIS units in the district itself.

(xiii) Rural Industrialisation campaign week is being celebrated from 15th March to 21st March 1979 in order to intensify the pace of Rural Industrialisation.

(b) No.

Under the Rural Industries Scheme, Govt. does not set up tiny units. The rural entrepreneurs are encourged to set up Industries the villages under the Rural Industries Scheme. A target of setting up 360 units has been fixed for 1979-80.

Drain near Jakhal

255. Ch. Peer Chand: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the digging work on Rangoi drain has been started, if so, the length on which the digging work has been completed;

(b) if the reply to part(a) above is in negative, the time by which the digging work will be started together with the time by which it will be completed; and

(c) whether there is any likelihood that the 18 villages inundated in the last rainy season will not be inundated during the coming rainy season in July 1979 ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(क) नहीं।

(ख) योजना छानबीन के अधीन है और इस पर कार्य केवल बाढ नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जा सकेगा। इसलिए इस स्थिति में निर्माण का निि चत समय बताना सम्भव नहीं है।

(ग) स्थिति को पूर्ण तरह ध्यान में रखा जायेगा और स्थानीय सहायता तीरके जहां आव यक होंगे लिये जायेंगे।

Amount advanced to Punjab for digging the S.Y.L. Canal

265. Ch. Peer Chand. Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Haryana Government has advanced a sum of Rs. one crore to the Punjab Government for digging the Sutlej Yamuna Link Canal; and

(b) if so, the total amount out of that referred to in part (a) above that has been spent so far ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह) :

(ए) हां

(बी) जो रा ि ा पंजाब सरकार ने व्यय की है, उसके बारे में उन्होंने कोई सूचना नहीं दी।

Cases of Murders, Dacoities and Thefts

266. Ch. Bhag Mal: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of cases of murders, dacoities and thefts registered during the years 1975-76, 1976-77, 1977-78 and 1978-79 respectively; and

(b) whether the number of crimes referred to in part(a) above is higher in 1978-79 than those in any other year during the above mentioned period, if so, the reasons thereof ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

		1—4—75 से 31—3—76	1—4—76 से 31—3—77	1—4—77 से 31—3—78	1—4—78 से 28—2—79
(अ)	हत्या	182	182	244	272
	डकैती	10	5	21	21
	चौरी	2692	2260	4689	3899
(ब)	अपराधों में प्राथमिक वृद्धि मुकद्दमों को मुक्त रूप से दर्ज करने के कारण है। तदनंतर चौरी के मुकद्दमों में प्र ांसनीय कमी हुई है। मानव विरूद्ध अपराध स्वाभाविक अपराध हैं और सुरक्षात्मक धाराओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त भी इस में अस्थितरा (उतार चढाव) हो सकते हैं।				

Increasing the strength of the Members of

Haryana Public Services Commission

267. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Chief Ministeer be pleased to state-

(a) whether the strength of members of the Haryana Public Service Commission has been increased some time back from three members;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any demand for increasing the strenght was made by the Public Service Commission ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) जी हां।

(बी) ताकि आयोग कार्यकु ालता बढा सके और काम का निपटान अधिक भीघ्रता से कर सके।

(सी) जी नहीं।

Strength of the Members of Subordinate Services

Selection Board, Haryana

268. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Chief Minister be pleased Selection Board has beed increased some time back from three members;

(b) if so, the reasons therefor;a nd

(c) whether any demand for incrasing the strength was made by the Haryana Subordinate Services Selection Board ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) जी हां।

(बी) ताकि बोर्ड कार्यकु ालता बढ़ा सकें और काम का निपटान अधिक भीघ्रता से कर सके।

(सी) जी नहीं।

Production of Sugar Cane, Cotton and Potatoes

269. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether the production of sugar cane, cotton and potatoes increased or decreased during the year 1978-79 as compared to that in 1976-77 and 1977-78;

(b) the year wise detail of production of the said crops together with the reasons of increase and decrease thereof in each case; and

(c) whether the farmers got more rated or less rated in 1978-79 as compared to the rates during the above mentioned period of two years and if they have got less rates, the steps taken buy the Government for giving reasonbale rates to the farmers in the State ?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):

(क) तथा (ख) तीनों फसलों का वर्शवार उत्पादन निम्न प्रकार हैं :–

	1976–77	1977–78	1978–79 (अनुमानित)
गन्ना (लाख टनों में)	72.80	89.70	85.00
कपास (गांठें 000 में)	478	464	500
आलू (टनों 000 में)	190	184	270

आलू तथा कपास का उत्पादन पिछले दो वर्श की अपेक्षा अधिक हुआ है जबकि गन्ने का उत्पादन पिछले वर्शों की अपेक्षा कुछ कम हुआ है।

(ग) पिछले 2 वर्शों की अपेक्षा इस वर्श फसलों के मूल्यों में आमतौर पर कुछ कमी हुई है। राज्य सरार चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य पर 4 करोड रुपये की रियायत दे रही है। नये कोहलुओं की स्थापना पर भी गन्ना उत्पादकों को रियायत दी जा रही हैं राज्य में हैफड/नैफड के

सहयोग से आलुओं की खरीद कर रही है ताकि खुले बाजार में आलुओं के बिक्री मूल्य में कुछ सहायता मिल सके। जहां तक कपास का सम्बंध है, भारतीय कपास निगम, कपास के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए कपास की खरीद कर रही है। इस उद्दे य के लिये हैफड ने भी कपास की खरीद की है।

Lease of Land for Twenty years

270. Ch. Peer Chand: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of teh Government to confer ownership rights on the persons who are holding lands on twenty years lease basis;

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the manner in which the persons referred to above will be required to make payments in respect thereof; and

(c) the time by which the proposal referred to in part (a) above is likely to be materialized ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) नहीं जी।

(बी) प्र न नहीं उठता।

(सी) प्र न नहीं उठता।

Naib-Tehsildars in the State

271. Ch. Peer Chand: Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of Naib-Tehsildars working in the Revenue Department at present together with the number of persons belonging to the Scheduled Castes amongst them ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(1) राजस्व विभाग में कार्यरत नायब तहसीलदारों की संख्या 97

(2) (1) में से अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या 17

राज्यपाल का संदे ा

15.00 बजे।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, राज्यपाल महोदय का मैसेज आया है, मैं इसको आपके सामनग पढ़ देता हूं :–

"I write to acknowledge with thanks receipt of demi-official letter No. HVS-LA-2-79/6621, dated 7th March 1979, forwarding a copy of the motion of thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on 6th March 1979. Please convey to the members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for this kind thoght in accepting the Motion."

कृशि मंत्री द्वारा वक्तव्य– कृशि उपज की कीमतों के बहुत ज्यादा गिरने सम्बंधी

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister of Agriculture is to make a statement in ragard to *Call Attention Motion regarding slump in the prices of agricultural produce. He may please do so.

कृशि मंत्री(ब्रिगेडियर रण सिंह): हरियाणा सरकार ने तरक्की की सब योजनाओं में खेतीबाडी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। इसका अन्दाजा इस बात से लगता है कि 1254 करोड रुपये

के छठे पांच साला प्लान में से 72 फीसदी हिस्सा खेतीबाडी या वो चीजें जो खेतीबाडी के काम आती हैं, उन पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 1979–80 की 227 करोड रुपये की सालाना प्लान में से 171 करोड रुपये खेतीबाडी और इससे जुडे हुए कामों पर खर्च किए जाएंगे।

यह तो सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हरियाणा किसानों भइयों की भलाई के कामों में जो कदम उठा रही है। वह एक निराली मिसाल है। हम यह मान कर चलते हैं कि जब कि किसानों की माली हालत में सुधार न होगा, तब तक दूसरे वर्गों का कल्याण मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ जहां किसान खु ाहाल होगा वहां दूसरे वर्ग की खु ाहाल हो जाएंगे। यह कहना सच होगा कि हरियाणा में किसन माली तरक्की के ढांचा में रीढ की हड्डी की हैसीयत रखता है। यही वजह है कि सरकार किसानों को खेतीबाडी में काम आने वाली चीजों, मसलन खाद बीज पानी और बिजली वगैरा की पूरी सप्लाई के लिए हर मुमकिन कोि ा ा कर रही है। हमारे लिए फख्र की बात है कि हरियाणा में खेतीबाडी की तरक्की दूसरे प्रान्तों के लिए एक नमूना है और आज हरियाणा अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा अनाज पैदा करने लगा है। यहां यह बात काबले जिक्र है कि हरियाणा में गेहूं, धान, कपास गन्ना और आलू की पैदावार में बेहद इजाफा हुआ है।

फसलों की फालतू पैदावार को खरीदने और स्टोर करने के लिए भी हरियाणा सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं।

जैसे केन्द्रीय सरकार से मुनासिब कीमतें मुकर्रर करवाना और उनकी वसूली और स्टोर करने के लिए खास सहूलियत दी गई है। धान और गेहूं की कीमतों के इलावा मोटे अनाज जैसे बाजारा, चने वगरा की भी केन्द्रीय सरकार से मुनासिब कीमतें मुकर्रर करवाई गई हैं। मिसाल मे तौर पर 1967 से 1974 तक वीट की प्रोक्योरमैंट प्राईस 76 रुपये रही और इन 7 सालों में कोई बढौतरी नहीं हुई। आपको याद होगा 1975 में जब खाद की कीमत ओवरनाईट डबल हो गई, तो इस प्राइैस में 29 रुपये फ्री क्विंटल इजाफा किया गया था और 1975 से 1977 तक यह 105 रुपये रही। इसके बाद 1978 में यह 112 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल फिक्स की गई जिसका मतलब यह है कि जनता सरकार के पावर में आने के बाद 105 रुपये से 112 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि और भी कीमत बढवायेंगे। इसी तरह 1977 में चने की कीमत 90 रुपये फिक्स थी और हमने 1978 में उसको 95 रुपये किया और 1979 में 140 रुपये किया गया है। इस तरह दो सालों में 50 रुपये बढी है। इसी तरह बाजरा को लें। इसमें पिछली सरकार ने 1967 से 77 तक यानी 10 सालों में सिर्फ 20 रुपये का इजाफा किया लेकिन जनता सरकार ने 1978 में इसकी प्राईस 85 रुपये फिक्स की, यानी एक साल में ही 11 रुपये का इजाफा किया।

इसके इलावा सरसों की कीमत 245 रुपये फ्री क्विंटल पहली बार मुकरर्र करवा दी गई है इससे हरियाणा के बारानी

इलाके के किसानों को खास तौर पर जहां यह फसलें काफी रकबा में बोई जाती हैं, फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस साल गेहूं की स्पोर्ट प्राईस भी बढवाने में कामयाब होंगे।

आप जानते हैं कि सरकार ने मिलों के गन्ने की खरीद का भाव साढे 12 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर करवा दिया है जिसकी वजह से सरकार को 4 करोड रुपये से ज्यादा घाटा उठाना पडा है। इसके इलावा नये कोहलू लगाने के लिए हमने किसानों को 50 लाख रुपये की छूट दी है। इसके इलावा बीज, खाद, जिप्सम और दवाईयों के लिए सरकार ने 1978 के मुकाबले में इस साल 1 करोड रुपये की फालतू छूट दी है। यानी इस साल 4 करोड रुपये की छूट दी गई है। मैं मानता हूं जैसा कि मैम्बर साहिबान जातने हैं कि इस साल कपास के भाव बहुत कम रहे हैं। कपासी की खरीद काटन कारपोरे ान आफ इंडिया करती है और सरकार ने इस पर सही भाव के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला है। इस मामला में हमने एक अहम उळाया है यानी हैफड को एक करोड रुपया देकर इसके द्वारा कपास की खरीद करा इंतजाक किया है और अब तक 12 हजार गांठें खरीदी जा चुकी हैं आप इस बात से सहमत हौंगे कि सरकाचर ने यह एक अनोखा कदम उठाया है और हम यह भी सोच रहे हैं कि आयंदा हम सारी कपास की पैदावार को खुद खरीदें ताकि किसान को मनासिब कीमतें मिल सकें।

आलू की खरी के बारे में भी हमारी हैफड ने 17 फरवरी से काम भुरू कर दिया है और मुझे यह बताते हुए बडी खु ाी महसूस होती है कि इसकी वजह से आलू का भाव 25 रुपये से बढकर 35–40 रुपये फी क्विंटल तक पहुंच गया है। मैं यह मानता हूं कि आलू की स्टोरेज के लिए हमारे पास काफी कोल्ड स्टोर्ज नहीं है जिनको बढाने के लिए सरकार गौर कर रही है। हमारी सरकार आलू की एक्सपोर्ट के लिए भी केन्द्रीय सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दवाब डाल रही है और हम भी पंजाब सरकार से मिलकर एक ऐसा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं कि हम खुद ही दूसरे मुल्कों में आलू और दूसरी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें।

गन्ना, कपास और आलू की कीमतों में जो कमी हुई है उसका सरकार को पूरा एहसास है लेकिन ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं हुआ है बल्कि सारे दे ा और बहुत से दूसरे मुल्कों में भी यही हाल है। ऐसी हालत में हमारी सरकार के लिए यह ममकिन नहीं कि वह इन तमाम चीजों की स्पोर्ट प्राईसिज मुकर्रर कवा सके लेकिन इसके लिए हम पूरी कोि ा ा करेंगे। खेती की पेदावार की कीमतों को बढाने में सबसे बडी मु कल अनाज के मामला में कमी वाले प्रान्तों की तरफ से मुखालफित है। भारत सरकार ने हाल ही में तम्बाकू पर से एक्साईज डयूटी हटा कर और खाद की कीमतों में कमी करके किसानों को जो 225 करोड रुपये की भारी छूट दी है। वह इस बात की सुनहरी मिसाल है कि जनता सरकार

किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाने में कितनी लगन रखती है। इसके अलावा किसानों को कुछ एक्साईज इन्सपैक्टरों की बदअनवानियों और ज्यादतियों से निजात मिलेगी।

हरियाणा सरकार किसानों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए भारत सरकार से लगातार तालमेल रख रही है। इस सिलसिले में केन्द्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इस बात की हर मुमकिन कोि ा ा की गई है कि अनाज के लाने और ले जाने के लिए रेलवे वैगन्ज की कमी न आए। अनाज की खरीद के काम में कोई मुि कल या ढी ल न आन पाये। इसके साथ ही इस बात की भी पूरी कोि ा ा की जा रही है कि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमतें मिलें। यह मामला कई बार मुख्यमंत्री जी के लैवल पर भी उठाया गया है और पूरी कोि ा ा की गई है कि मौजूदा हालात मे किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें और सहायता दी जाए।

अगरचे हरियाणा में खेतीबाडी में बडी भारी तरक्की हुई है लेकिन इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारी यह पूरी कोि ा ा है कि फालतू पैदावार होने पर कीमतों में कमी बिल्कुल न आने दी जाए। मैं मैम्बर साहिबान को यकीन दिलाता हूं कि हम इस भाुभ काम में जरूर कामयाब होंगे।

Mr. Speaker: Shri Har Swarup Bura, who moved this motion can ask one/two quesitons.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, क्या मुझे भी एक सवाल पूछने का मौका देंगे ?

श्री अध्यक्षः रूल्ज के अनुसार जा मैम्बर काल अटैन ान मो ान मूव करता है सिर्फ वही सवाल कर सकता है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, जहां तक जवाब देने का ताल्लुक है कृशि मंत्री जी का उत्तर बडा संतोशजनक है लेकिन मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि गेहूं का और ज्यादा भाव दिलाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है परन्तु क्या मंत्री जी यह आ वासन देंगे कि गवर्नमैंट जो स्पोर्ट प्राईस फिक्स करेगी यदि कीमत उससे नीचे आ जाए तो सरकार गेहूं को खुद खरीदेगी क्योंकि इस बार बम्पर क्रौप होने जा रही है ?

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, अपने भाई चौधरी बूरा जी कौ मैं वि वास दिलाना चाहता हूं कि अगर फिक्स की गई स्पोझर्ट प्राईस से नीचे कीमत गिरती है तो सरकार फौरन मैदान में आ जाएगी।

श्री कंवल सिहः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब मैं कहा है कि भाूगर केन, कौटन और पौटटो की कीमतें सारे संसार में गिरी हुई हैं। मुझे नहीं पता कि किस आशार पर उन्होंने ऐसा कहा है। यह तो मैं मान सकता हूं कि भाूगरकेन और पोटैटो की प्रोडक ान में

ग्लट हो लेकिन कौटन का जहां तक संबंध है इसके बारे में हमने अखबारों में पढा है कि कौटन की कमी की वजह से पाकिस्तान ने मलेि ाया और सिंगापुर वगैरह को कौटन देने से इंकार कर दिया था। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसके बारे में मंत्री महोदय से और स्टडी करवाएं।

ब्रिगेडियर रण सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अपने बयान में कुछ मुल्कों में कहा है, सब मुल्कौं में नहीं।

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान बिल 1979

Mr. Speaker: Now a Minister will introduce the Haryana Appropriation Bill.

वित्त मन्त्री (श्री मूल चन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हरियाणा विनियोग विधेयके 1979 प्रस्तुत करता हूं :—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

कि हरियाणा विनियोग विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion move-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

साहेबान आपको मालूम है कि सप्लीमैंअरी ऐस्टिमेटस के ऊपर दो तीन घंटे की डिस्क ान हो चुकी है और बहुत से साहेबान उसमें भाग ले चुके हैं। उन साहेबान के अलावा यदि कोई और साहेबान इस वक्त बोलना चाहें तो वे बोल सकते हैं।

(अस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने पिछले दिनों 35.95 करोड रुपये के अनुपूरक अनुमान रखे गये। यह राज्य के ऊपर एक प्रकार से काफी बडा खर्चा है क्योंकि इस पैसे को काफी सोच विचार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय, की दवाईयों का खर्च 10900 रुपये रखा गया है जबकि सारे हरियाणा में एक लाख व्यक्तियों कै पीछे केवल 70 बिस्तरों का इन्तजाम है। मैं समझता हूं कि यह हरियाणा की जनता के साथ न्यायसंगत बात नहीं है। यही नहीं सारे हरियाणा में तो प्रति व्यक्ति दवाई का खर्च 50 पेसे से 75 पैसे तक पडता है लेकिन दूसरी तरफ आप देखें दो व्यक्तियों के ऊपर 10900 रुपये पडता है। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की भावनाओं के अनुकूल यह खर्च नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनुपूरक मांगों में जल विरण की जो योजनाएं हैं उनकी मुरम्मत करने के लिए 12 लाख चालीस हजार रुपया रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, गुडगांव जिले में बहुत सारी योजनाएं ऐसी पडी हुई हैं जिनकी काफी अर्से

से मुरम्मत नहीं हो पाई है। लेकिन उसके लिए एक पैसा नहीं दिया गया। यह 12 लाख 40 हजार रुपया कहां गया, किस रूप में गया यह बात समझ में नहीं आ रही है। जब हम इसके बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है कि सन 82 तक सब गांव में पानी दे देंगे ओर सब गांवों में सडकें दे देंगें। उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदन के सामने जो बात रखी गई वह यह है कि एक साल के अंदर साढे सात करोड रुपये खर्च करके केवल 125 गांवों को पानी दिया गया बाकी सारे क्षेत्रों को छोड दिया गया। पिछले 19 महीनों में गुडगांव जिले के एक भी गांव में पानी नहीं दिया गया। सारा पैसा कहां जा रहा है यह बात सदन के सामने साफ प्रकट नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पिछले दिनों नगीना और पीपली में लोगों के साथ काफी ज्यादती हुई थी। उसके लिए एक जांच आयोग जिसका नाम भार्मा आयोग था बैठाया गया था। उसके ऊपर 547210 रुपये खर्च किए गए। माननीय भार्मा जी ने ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस ज्यादती के लिए मुख्य अधिकारी दोशी हैं और उनको सजा दी जानी चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि नगीना फायरिंग के लिए जो अधिकारी दोशी थे उनका पूरी तरह समर्थन किया गया और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, सडकों की बात है। बाढ से जो सडकें टूट गई थी उनकी मरम्मत के लिए 55 लाख

16 हजार रुपये खर्च किए गए। इसके बारे में भी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गुडगांव जिले में बहुत सारी सडकें टूटी पडी हैं जैसे बरौट, खोकियाका, बामनी खेडा,ख हसनपुर, होडल, नूंह, मलाई, अलालपुर। उपाध्यक्ष महोदय, बामनी खेडा से हसनपुर वाली सडक पिंगौड के पास टूटी पडी है लेकिन पिछले दस साल से हम देख रहे हैं कि 250 गज की इस सडकी की कोई मुरम्मत नहीं हो पा रही है जबकि 55 लाख 16 हजार रुपया बाढ से टूटी हुई सडकों के लिए खर्च किया गया है।

इसी तरह से सडक के ऊपर जो पुल टूटेम हुए थे उनके लिए 24656000 रुपये खर्च किए गए हैं लेकिन इस दि ाा में भी गुडगांव जिले का इग्नोर किया गया है। वहां बहुत से पुल टूटे हुए हैं जैसे रानिका ड्रेन का पुल है, उटावड रजबाहे पर पुठली और रुपडा का पुल है, गांची ड्रेन पर कुंडल का पुल है। ग्रिवैंसिज कमेटी में भी मैंनें यह बात उठाई थी लेकिन अभी तक इस दि ाा में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इनके अलावा कई और मुख्य स्थानों पर भी पुल टूटे हुए हैं लेकिन उनकी तरफ भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए यह 24656000 रुपया भी पता नहीं कहां खर्च हो रहा है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान स्कूलों की मुरम्मत की और आकर्शित करना चाहता हूं। 20 लाख रुपये का प्रावधान पिछले सप्लीमैंटरी ऐस्टिमैंटस में किया गया था और 20 लाख रुपये का प्रावधान अब की बार किया गया है। उपाध्यक्ष

महोदय, ये मेरे पास कुछ स्कूलों के फोटोग्राफ्स हैं जैसे औरंगाबाद, खाईका, खटैला, बहीन, सोंध, कंडल और मलाई के स्कूल। इनकी हालत बडी खस्ता है। इसलिए यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। यह बात तो दुरस्त कहते हैं कि गांवावें को हित चाहते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूलों के लिए बहुत सारा रुपया रखा गया है लेकिन हमारे इलाके में स्कूलों की वही हालत है जैसे पिछले साल बाढ के कारण थी। मैं इस समय हाई स्कूलों और हायर सैकेण्डरी स्कूलौं की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये प्राईमरी स्कूल पिछले दो सालों से गिरे पडे हैं। पिछले सै ान में भी इन स्कूलौं के लिए रुपया रखा गया था लेकिन औरंगाबाद के स्कूल की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है जबकि करोडों रुपया सरकार खर्चा करने जा रही है। जहां पर पैसा खर्च करने की आव यकता है वहां पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 लाख 42 हजार रुपया बच्चों के भोजन के लिए रखा गया है जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्कूलों में भोजन की क्या व्यवस्था है ? वहां पर जिस प्रकार का भोजन दिया जाता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक मांगों में पुलिस के 4976515 रुपया पुलिस पोस्टस के लिए और उनके मकानात बनाने के लिए रखा गया है। आपको जानकर यह हैरान होगी कि जुलाई के महीने में पोखर दास को जो कि बाद ाहपुर गांव का रहने

वाला था मारा गया। उसकी जिस ढंग से हत्या की गई है उससे प्रतीत होता है कि पुलिस कुछ भी प्रबंध नहीं कर रही है। उसके भारीर को रस्सियों से बांधकर और मुंह में कपडा ठूंस कर के खत्म कर दिया गया। आज तक उन व्यक्तियों का पुलिस पता नहीं चला पाई। कितनी ही बारे में पहले सरकार के नोटिस में यह बात लाई जा चुकी है लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई एक ान नहीं लिया जा रहा है। आसपास के लोगों को यह भय हो गया है कि अगर पोखर दास की हत्या हो सकती है तो हमारी जिंदगी भोफ नहीं है। जब भी कभी यह सवाल उठाया गया है तो इस हत्या का रहस्य ही बना रहा। इसकी आज तक कोई भी छानबीन नहीं हुई।

इसी प्रकार से गांव मोहबताबाद में 9 फरवरी को भयामवती हरिजन लड़की के साथ कुछ नालायक व्यक्तियों ने बलात्कार किया जिसको कारण वह भार्म के मारे कुएं में छलांग मार कर मर गई। जब मैंने और श्री गया लाल जी ने ग्रिविन्सिज कमेटी में यह सवावल उठाया तो जवाब मिला कि यह जो ि ाकायत की गई है यह औरतों की अपने ढंग की है। उस ि ाकायत के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, कोई एक ान नहीं लिया गया। तीसरा केस श्री लीला राम बावरिया का है जो कि गांव मरौली का रहने ववाला है। हजूर सिं हए0एस0आई0 (महेन्द्रगढ) ने उसको बुलाया और उससे चार हजार रुपये मांगे थे जिसमें से दो हजार तो उससे ले लिए गये लेकिन उस गरीब को फिर भी तंग

किया जा रहा है। उसके गांव के सरपंच ने भी लिख कर दिया है कि इसका कोई कसूर नहीं है परन्तु फिर भी उसको तंग किया जा रहा है और सारे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है। सरकार कहती है कि हम गरीबों को न्याय दिलायेंगे जबकि जनता के खून पसीने की कमाई को बेरहमी के साथ खर्च किया जा रहा है। किसी के साथ कोई न्याय नही ंकिया जा रहा है और न ही पैसे का ठीक प्रकार से प्रयोग से प्रयोग किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक मांगों में भी और पिछले सै ान में जा अनुपूरक मांगें आई थी उनमे भी आतिथ्य स्वागत के लिए काफी पैसा खर्च किया गया था। जब चण्डीगढ़ में कोई बाहर के अतिथि आये तो उन पर दो लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन टपरीवास विमुक्त जातियों के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है उधर सरकार ने वि ाश्ट व्यक्तियों के लिए दो लाख रुपया अतिथि सत्कार पर खर्च किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1 करोड 77 लाख रुपया गन्ने के लिए रखा है। जिन क्षेत्रों में गन्ने के मिल हैं उनके लिए यह व्यवस्था की गई है लेकिन जिन क्षेत्रों में मिल नहीं है वहां गुड मिट्टी के भाव से बिक रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। गन्ने से आज लोगों को नफरत हो चुकी है। एक तरफ तो सरकार अन्न ज्यादा उगाने पर जोर दे रही है। जब किसी भी अन्न का ज्यादा उत्पादन बढ जाता है तो कहते हैं कि इस फसल की वजह पर दूसरी फसल बोयचें क्योंकि इसका भाव मार्किट में गिर चुका

है और यह फसल ज्यादा मात्रा में आ रही है। अब आप ही बतायें कि किसान कहां जाये। सरकार ने जहां पर मिल लगाये हुए हैं वहां के लिए 1 करोड 77 हजार रुपया दिया है लेकिन जिन क्षेत्रों में मिल नहीं है वहां पर भी तो ठीक उसी प्रकार कोई प्रबंध होना चाहिए ताकि उसको गन्ने की या गुड की कीमत पूरी मिल जाती।

सरकार ने 1845000 रुनया आद र्ा गांव बनाने के लिए रखा है। 950000 रुपया माडल और फोकल गावों में पैरिफिरी रोड बनाने के लिए रखा गया है। इस बारे मे मेरा विचार यह है कि जिन गांवों को आद र्ा गांव बनाना है जिसको मंत्री महोदय चाहेंगे उसको बना दिया जायेगा। किसी वि ोश गांव को मंत्री जी चुन लेंगें और उसको आद र्ा गांव बना देंगें। इसी तरह से दस पन्द्रह गांवों की फिरनी बनाने के लिए सरकार ने 950000 रुपया रखा है जबकि डेढ हजार गांव ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल ही सडकें नहीं हैं। मुख्य मंत्री महोदय जी कहते हैं कि सन 1982 के चुनाव होने से पहले सभी गांवों को सडकों के साथ जोड दिया जायेगा। एक तरफ तो सरकार इन गांवों पर इतना रुपया खर्च कर रही है और दूसरी ओर कोई सडक का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। मेरे अपने हलके में कितने ही ऐसे गांव हैं जाहं पर सडकें नहीं हैं इसलिए पहले वहां पर सडकें बनायी जानी चाहिए बाद में आद र्ा गांवों में सड़कें बनाई जानी चाहिए। डाक्टर लोहिया जी कहा करते थे कि सरकार गुलाब के फूल उगाने जा रही है परन्तु उसके चारों तरफ जो गंदगी है उसको साफ नहीं करना चाहती है। वे

कहते थे कि पहले गंदगी को साफ करो और बाद में फूल लगा लेना। यह जो 950000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं इसमें से पक्षपात की बू आ रही है। दूसरे गांवों की कोई भी चर्चा नहीं है कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार से आवास के लिए बहुत ज्यादा रुपया रखा गया है। 95 लाख रुपया रखा गयार है लेकिन औरंगाबाद का एक व्यक्ति सन 1968 से लो इंकम ग्रुप के लिए पैसा मांग रहा है आज तक उसको पेसा नहीं मिला है। क्या यह 95 लाख रुपया बहुत अधिक है ?

हरिजनों की चौपालों के लिए भी काफी पैसा दिया गया है, यह बडी अच्छी बात है लेकिन बडी हैरानी की बात है कि जनता सरकार के आने के प चात किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनका बहुत ही बुरा हाल है। जैसे किसी भाायर ने कहा है :–

निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में,

मसीहा मसलेहत बी से रिन्दे ओ वायदा खबार अच्छां

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है वह किसी से छिपा हुआ नहीं अगर कोई काम इस सरकार से रह गया तो

हमे ाा के लिए वह काम रह जायेगा। इसलिए जब हम डाक्टर के सामने जायें तो हमारा फर्ज बनता है कि बीमारी को बतायें। जो भी कोई सरकार आगे आयेगी वह इतनी तेजी के साथ काम नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरे हलके में कुछ गांव ऐसे हैं जो रिकार्ड पर नहीं है। उन गांवों की बडी भारी पापुले ान है लेकिन वाह पर कोई सडक या डिवैल्पमैंट का काम नहीं हुआ है। अगर मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं कि उनके नाम गिनाओ तो मैं वह भी गिना सकता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदे ा से हवा चलती है। बारि ा भी उसी तरफ से आती है। हम पहाडों के नीचे बसते हैं और जब हिमाचल के लोग दिल्ली जाते हैं तो उनके रास्तें में डांगरी, ओमला और धनाना नदी पडती है जिनके कारण काफी दिक्कत होती है। पहले वाली सरकार चली गई उसने तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग छः महीने तक तो जिले से कटे रहते हैं यानि छः महीने तक न हम अपने अम्बाला जिले में जा सकते हैं और न ही अपनी तहसील में जा सकते हैं। वहां पर सरकार की तरफ से पुल बनाये जाने चाचहिये ताकि इन तीनों नदियों कोपार करने में लोगो को परे ाानी न हो। सरकार ने यह वायदा किया है कि हरिजनों को और बैकवर्ड लोगों को उठायेंगे लेकिन आज तक हमारे इलाके में जो लोग उन नालों की दराडों में गिर जाते हैं उनके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। वहां पर पक्की सडकें और गलियां बनायी जानी चाहिए।

पंचायत डिपार्टमैंट के सिवाए उन गांवों को कोई भी नहीं सम्भल रहा है। हमारी जो पुरानी पंचायतें हैं उनके सरपंचों के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमी ान नहीं बनाया गया है। वह वैसे के वैसे ही 30 साल से पब्लिक का पैसा खाए बैठे हैं उन्होंने गलियों को ठीक कराने का कोई काम नहीं किया। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वहां पर कोई भी साधन नहीं हैं। वहां पर टयूबवैल कामयाब नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पर पत्थर हैं। हमारी बहिनों और माताओं को हिमाचल के एरियामें पानी लेने के लिए जाना पडता है और उनकी हिमाचल के लोग बेइज्जती करते हैं। तो मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि सरकार उन लोगों को भी पानी की सुविधा दें। इस सरकार के जमाने में ही यह काम हो सकता है वरना कभी नहीं होगा। मेरे हलके में कई मिनिस्टर साहब भी देखकर आये हैं। मैंने मुख्य मंत्री महोदय जी से अपने हल्के के लोग भी मिलवाये हैं और इन्होंने यह हुक्म भी दिया है। गर्मी के मौसम में मेरे हल्के के लोग इधर पंजाब मे सतलुज के किनारे और उधर गंगा के किनारे चले जाते हैं। ये प ा बगैरा साथ मे लेकर चलते हैं। आधे प ा तो लो रास्ते में छीन लेते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि उनका बहुत बुरा हाल है। मेरी प्राथ्रना है कि वहां पर जो जोहड़ और छप्पड हैं उनकी मुरम्मत करवायी जाये ताकि वहां पर थोडा बहुत पानी रखा जा सके। वहां पर नहर का पानी थोडा बहुत जरूर पीने के लिय और खेती के लिये दिया जाये क्योंकि आपका पता ही है कि टयूबवैल तो वहां पर कामयाब नहीं हो सकते।

अब मैं सडकों की बात पर आता हूं पिछली सरकार ने एक पुल मेरी कांस्टीच्यूएंसी में बनाया था। वह पुल बहुत जल्दी टूट गया है। इन बात की कोई इंकवायरी नहीं हुई है कि वह टूट क्यों गया है? उसको बने अभी कुछ साल भी नहीं हुए हैं लेकिन वह टूट चुका है। इस बात की इन्कवायरी होनी चाहिए कि यह पुल कौन सेा चीफ मिनिस्टर के टाईम पर बना था। कौन मिनिस्टर उस वक्त इस डिपार्टमैंट का इंचार्ज था और क्यों इतनी जल्दी पुल टूट गया। पंचकूला से स्टेट हाईवे पर जो सडक वहां को निकलती है जो उसी पुल पर से होकर आगे जाती है कुछ अर्सा पहले यह पुल बना और इतनी जल्दी कैसे टूट गया। इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना बडा पुल है यह कैसे टूट सकता है। इसमें कोई हेराफेरी जरूर हुई है। अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि यह जो बागवानी का पुल है जो नारायणगढ और अम्बाला को जोड़ता है और हिमाचल से दिल्ली आने जाने का रास्ता है इसको बनाया जाये क्योंकि यही सरकार उसको बना सकती है और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वह इसको बना सके।

इसके अलावा हमारे यहां पर जो बसें दी गई हैं ये पीपों को रंग करके दिया गया था, इस बात की इंकवायरी होनी चाहिए कि किस कम्पनी से वे ली गई और किस आदमी के कहने पर वे ली गई और उसने उसमे कितना पैसा खाया। इस पर कोई न कोई एक ान अव य होना चाहिए। वे बसें अभी भी धुआं निकालती है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस

बारे में सरकार जल्दी ही कोई कमी ान मुकर्रर करे जो इस बात की जांच करें कि यह हेराफेरी कैस हुई और किसने की ? इसके अलावा मैं अपनी सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी तहसील नारायणगढ में कोई बस अड्डा नहीं है। पहले बनने लगा था लेकिन अब फिर बंद हो गया है। वहां पर बसें खड़ी करने के लिए कोई जगह नही है लोग बारि ा में कहीं पर खडे नहीं हो सकते। हिमाचल प्रदे ा हरियाणा के पडोस में है। दिल्ली जाने के लिए नारायणगढ से होकर ही उन लोगों को जाना पडता है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर एक बस अड्या जरूर बनना चाहिए।

जंगलात के महकमे का जहां तक ताल्लुक है, किसान अपने खेत में से मक्की काट सकता है, चना काट सकता है लेकिन वह खेत में खडी लकडी नहीं काट सकता। अगरवह काट सकता है तो वह गार्ड से मिलकर ही काठ सकता है। गार्ड वहां पर कन्जर्वेटर बना हुआ है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरपकार इस समस्या का भी कोई न कोई हल निकाले क्योंकि लोग इस वजह से बहुत दु:खी हैं और बहुत परे ाान हैं। दफा 4 एक किस्म का कलंक है। 1968 में जब मैंने रौला डाला तो उसके बाद एक चिट्ठी आयी कि यह हटा दी गयी है। यह चिट्ठी आयी थी कि रायपुर रानी से काले आम तक यह टूट गयी है। मेरी प्रार्थना यह है कि यह सरकार उसे खत्म करें। इससे खामखाह लोगों को परे ाानी होती है

सरकार ने यह आर्डर कर दिया है कि गन्ना मिलें अव य ही गन्ना खरीदेंगी। मैं इसकी तारीफ करता हूं लेकिन हमारे अम्बाला जिले में जो डी0डी0पुरी की गन्ना मिल लगी हुई है उसकी मौनोपली बनी हुई है। सरकार को वहां पर कोई सरकार मिल लगानी चाहिए वरना उस मिल को ने ानेलाईज करें। इस बात की भी सरकार मिल लगानी चाहिए वरना उस मिल को ने ानलाईज करें। इस बात की भी मैं मुबारिकबाद देता हूं कि यह हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी की ही हिम्मत है जो इन्होंने डी0डी0 पुरी जैसे आदमी से किसानों को 12 रुपये का रेट दिलवाया है। दूसरा कोई मुख्यमंत्री इस काम को कर भी नहीं सकता। इसलिये मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से यह प्रार्थना करूंगा कि श्री डी0डी0 पुरी की मिल की मनौपली को तोडा जाये ताकि जो वहां के जमींदार हैं, उनको कुछ फायदा हो सके वरना यह कलंक हमे ाा ही हमारे सिर पर लगा रहेगा। वहां पर कोई दूसरा मिल लगा नहीं सकता।

इसके अलावा हमरा अम्बाला जिला इस बात के लिए भी परे ाान है कि वहां सारे अम्बाला जिला के अंदर कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है। इस वजह से हमारे बच्चे पढ नहीं सकते। सारे अम्बाला जिले में पिछली सरकार ने लाला कि ाोरी लाल को खु ा करने के लिए एक कालेज दिया था जो कि हिमाचल के बराबर लगता है। कौन लड़का या लड़की वहां पर पढने के लिय जायेगी ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक सरकारी कालेज चाहे

आप नारायणगढ में या कही आस पास ही जहां कही भी आप उचित समझें अव य दिया जाये। इसके अलावा आपका पता है कि एक एक भैंस 5–5 हजार रुपये की आती है। इससे कम नहीं आती। 5000 से कम को कोई बल्द नहीं आता। अगर कोई पागल कुत्ता भैंस को काट ले तो उसके लिए हमारे यहां पर कोई दवा नहीं है हमें कसौली जाना पड़ता है। अभी परसों ही एक आदमी की दो भैंसे जो उसने अभी 25–25 सौ रुपये में खरीदी थीं मर गयीं क्येांकि वह जितनी देर में कसौली ले गया, उतनी देर में वे मर गई। इसलिये मेरी सरकार से दरख्वासत है कि पागल कुत्ता काटने की दवाई कम से कम नारायणगढ में अव य रख दी जाये ताकि इससे वहां के लोगों को फायदा हो सके। आपको पता ही है कि प ाुधन कितना महंगा है।

इसके अलावा नौकरियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिटायर होते जाते हैं। उनको बिजनैस में लगाया जाये और जो बच्चे बेकार घूम रहे हैं उनको नौकरी में लगाया जाये। इससे आपकी अनएम्पलायमैंट की प्रौब्लम सौल्व होगी। तहसील नारायणगढ का जो ढांचा है, वह सुधरना चाहिए। पीने के लिए पानी वहां पर नहीं है, चलने के लिये सडकें वहां पर नहीं है रहने के लिए मकान नहीं है पढने के लिये कालेज नहीं हैं इसी वजह से वहां की हालत बहुत खराब है। अगर उस तहसील में यह चीजें देंगे तो वहां के लोग आपके गुण गायेंगे। 30 साल तक यह इलाका पिछडा रहा है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि

नारारयणगढ को आप करनाल की तरह से आगे ले जायें, बहुत कमजोर तहसील है। बहुत गरीब तहसील है और यह पापुलर सरकार है आज तक वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ हौ। इस पापुलर सरकार का फर्ज बनता है कि वहां पर कोई न कोई काम अव य करें।

एक बात और मैं सरकार से कहना चाहता हूं जब हम लोग जेलों में थे तब हमें फटे कम्बल दिये जाते थे लेकिन इन लोगों के लिये कितनी ज्यादा सहूलियतें आप दे रहे हैं यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अब्बल मेें तो आपको पकडने नहीं चाहिए और अगर आप किन्हीं लोगों को पकड लेते हो तो आपको उन्हें छोडना नहीं चाहिये। अंत में मैं आपका भाुक्रिया अदा करते हुए इतना कह कर ही समाप्त करता हूं कि जो पिछली सरकार के सरपंच हैं, उन्होंने पैसा बहुत खाया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये चाहे आप कोई आई0ए0एस0 आफिसर बिठाकर इनकी इंकवायरी करवायें लेकिन इनकी इंकवायरी अव य होनी चाहिए। इसके अलावा नाराणगढ तहसील की तरक्की के लिए आप कुछ न कुछ अव य करें। धन्यवाद।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह(उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो अनुपूरक मांगें हैं जिनके बारे में चौधरी लाल सिंह ने चर्चा की और उन्होंने दूसरी बातें भी की उनमें 36 करोड रुपए के लगभग ऐसी मांगें हैं जिनको सदन के सामने रखा गया

है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन डिमांडज में से डिमांड नम्बर 25 ऐसी हैं जिसके द्वारा कार्पोरे ांज की और दूसरी ऐसी संस्थाओं को जो सैमी गवर्नमैंट हैं उनको लोन्ज या ऐडवांसिज के रूप में रुपया दिया गया है। इस में से सब से ज्यादा पैसा नौ करोड हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में कम से कम 34 ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐटोनोमस बौडी हैं जैसे मार्किटिंग बोर्ड, हरियाणा ऐग्रो इंडस्ट्रीज, माईनर इरीगे ान टयूबवैल्ज कार्पोरे ान इत्यादि। इन संस्थाओं को हरियाणा सरकार ने कई सौ करोड रुपया ग्रांट की भाक्ल में या लोन की भाक्ल में दिया हुआ है। जब बजट पर चर्चा होगी तो इस विशय में मैं अलग से चर्चा करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, ये सारी कार्पोरे ांज और बोर्डज कम्पनी ला के तहत रजिस्टर्ड हैं और हर साल इनकी बैलेन्स भीट बनाई जाती हैं। अगर इस सदन की एक कमेटी बनाई जाए या सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए तो पता लग जाएगा कि हरियाणा की जनता का जो करोडों रुपया इन बोर्डज और कार्पोरे ांज में हरियाणा सरकार इंवैस्ट कर चुकी है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। नौ करोड से ज्यादा का लोन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को हरियाणा सरकार दे रही है और डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक उदाहरण इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम करने के तरीके का देना चाहता हूं। हरियाणा राज्य के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का थर्मल प्लांट जो फरीदाबार में कार्य कर रहा है और जो बहुत पुरानी है उसकी

मैंटीनैंस के लिए, उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिये हरियाणा राज्य के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास ऐसे इंजीनियर्ज ही नहीं हैं जो उसको ठीक प्रकार से चला सकें। पता नहीं कि हमारे इंजीनियर्ज को उस थर्मल प्लांट को चलाने के बारे में ज्ञान ही नहीं है या कोई और हेराफेरी है। बिजली बोर्ड ने बी0एच0ई0एल0 को उसकी मैंटीनैंस का कांट्रक्ट दिया हुआ है। बडी अजी बात है कि हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर उसके अधिकारियों पर करोडों रुपया खर्च किया जाता है, उसके इंजीनियर्ज पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन वे उस र्थल पलंट की मैंटीनेंस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे अपने काम के अंदर पूरी तहर से ऐक्सपर्ट नहीं हैं और उनका जो भी प्रोजैक्ट हरियाणा के अंदर लगाया जाता है जिसमें जनरे ान होती है उसकी मैंटीनैंसे वे नहीं कर सकते हैं। यह बात मानने योग्य नहीं है कि हमारे इंजीनियर्ज उस थर्मल प्लांट को चलाने में अयोग्य हैं चौदह लाख रुपये का तो मुझे पता है कि ऐी0एच0इ0एल0 का कांट्रैक्ट है, हो सकता है कि ज्यादा रुपया भी दिया गया हो। इसी प्रकार से पानीपत में जो थर्मल प्लांट बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक ान के लिए भी वोलटाज, टेलको और टाटाज जैसी बडी बडी फर्मों को करोडों रुपए का ठैका दिया गया है। मेरा सदन को बताने का मतलब यही है कि इस प्रकार की अनियमिताएं बोर्ड के कामकाज में हो रहीं हैं यहां पर घोटाल हो रहे हैं और करोडों रुपए का इसमें प्रोविजन किया गया है। अढाई करोड रुपया उनसे इंट्रैस्ट की भाक्ल में लेना था लेकिन वह भी ऐडजस्ट हो जाएगा।

कुछ रुपया और भी एडजस्ट हो जाएगा, सरकार को केवल अढाई करोड रुपया देना पडेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि जो कार्पोरे ांज हैं या बोर्ड हैं इनकी बेलेन्स ाीट इस प्रकार तैयार की जाती है कि उनमें घाटा दिखाया जाता है। इनमें हरियाणा की जनता का करोडों रुपया लगा हुइा है और ये कमि र्यल आर्गेनाइजे ांज हैं, अगर इनमें घाटा भी हो तो कोई बात नहीं है लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन की या सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए और वह कमेटी इन कार्पोरे ांज और बार्डज की जांच करें। हरियाणा की 34 कार्पोरे ांज और बोर्डज जो कमि र्यल तौर पर चलाये जाते हैं उनसे सरकार को करोडों रुपये की आमदनी हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर के हैड के अंदर दो करोड से ज्यादा की मांग की गई है। इसमें सबसे ज्यादा रुपया यानी 1 करोड 77 लाख रुपया भ्ागर मिल्ज को लोन की भाक्ल में या सबसिडी की भाक्ल में दिया गया है क्योंकि इन मिल्ज ने किसानों को रुपया देना है और उस घाटे को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने रुपया दिया है ताकि वे मिल किसानों को गन्ने का पूरा भाव दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से किसान को मिल से पूरा भाव मिल जाएगा लेकिन दूसरे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। एक तरफ तो सरकार पौने दो करोड रुपया किसानों को पूरा भाव देने के लिए मिलों को पैसा दे रही है और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, सात तारीख को जब बजट

पे ा किया गया तो दस करोड के टैक्सों में से कम से कम आठ करोड के टैक्स केवल किसानों के ऊपर लगाए गए हैं पौने दो करोड रुपया केवल इसलिए देना कि किसानों को गन्ने का पूरा भाव मिले और दूसरी तरफ उन पर टैक्स लगा देना यह तो वह बात हो गई कि एक तरफ से निकाल कर दूसरी तरफ दे रहे हैं। जब सरकार मिलों के घाटे को पूरा करने के लिए मिलो को सबसिडी दे रही है तो बजट में जो घाटा बढेगा और उस घाटे को पूरा करने के लिए हरियाणावासी पर, गरीब मजदूर पर, किसार पर टैक्स लगाए जाएंगे। इस तरह से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह भारत सरकार से बातचीज करें और भारत सरकार को विव ा करे कि किसानों को गुड और गन्ने का पूरा भाव दिलायें। अगर हिन्दुस्तान में उसका पूरा भाव नहीं मिलता तो ऐसा प्रावधान किया जाए कि गुड या चीनी दे ा से बाहर जाएं जिससे कि इन चीजों के भाव बढ सकें और किसानों की जेब में पैसा आ सके। जब किसाने की जेब में पैसा आएगा तो किसान की खु ाहारी बढेगी। किसान की खु ाहाली बढने से दे ा की खु ाहाली बढेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि सरकार ने 49 लाख से भी ज्यादा रुपया होम डिपार्टमैंट के लिए मांगा है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स को बढाया गया है। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को कहूंगा कि जिन लोगों ने उनके पास बैठकर यह कहा है कि आज के दिन

हरियाणा के अंदर भ्रश्टाचार खत्म हो गया है या कम हो गया है या हरियाणा के कर्मचारी और खास तौर पर पुलिस कर्मचारी ईमानदारी से नेक नियती से गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल गलत बात करते हैं और बिलकुल निराधार बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसी सिलसिले में एक अपने हल्के उचाना की ही मिसाल देताह ूं आज से 10–15 दिन पहले मेरे हल्के में एक डकैती पडी और इसके बारे में जब वहां के लोग रपट लिखवाने गये तो वहां की पुलिस ने कहा कि तेरा केस अच्छा मजबूत बनवाएंगे और जिन आदमियों का इस डकैती में हाथ है, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस काम के लिये उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों से 2300 रुपये जेब गर्म करने के लियै रि वत के तौर पर लिये गये। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ गई है, रि वत खोरी को बढावा मिल रहा है, भ्रश्ट आदमियों को बढावा मिल रहा है प्र ाासन को कोई रोब नहीं रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज दफतरों में भी बहुत बुरी हालत है। आप दफतरों में चले जायें, वहां भी लोग कहते हैं कि पैसा लेकर आईये तब आपको काम होगा। आज लोगों के अंदर एक किस्म की दह ात सी हैं जनता सरकार ने अपने घोशणा पत्र में यह कहा था कि किसी आदमी को किसी किस्म का भय नहीं रहेगा, सब ाक भय दूर हो जाएगा लेकिन आज भय चोरों का, लुटेरों का और भ्रश्ट आदमियों का दूर हो रहा है। गरीब आदमी इस प्र ाासन में बुरी तरह से पिस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हालात बहुत बिगड चुके हैं। पिछले 15 दिनों में रोहतक में चार कत्ल हुए हैं, जिला जीन्द में 3 डकैतियां हुई हैं और ये वाक्या बडे सनसनीखेज हैं कि एक डकैती में तो औरतें भी डाका मारने गई। कहने का मतलब यह है कि हरेक जगह पर लोगों का भय मिट गया है और रि वत का बाजार भी खूब गर्म हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रावधान में जो 50 लाख से कुछ कम रा ि ा मांगी गई है, वह पुलिस की न भर्ती के लिये और प्र ाासन को स्वच्छ व ऊपर उठाने के लिये मांगी गई है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो भ्रश्ट अधिकारी हैं जिनकी इंटेगरिटी औ आनेस्टी पर सन्दे हो, उनको छोड न जाए और उनके खिलाफ पूरे जोर भाोर से कार्यवाही की जाए ताकि दूसरे कर्मचारियों को भी इससे सबक मिल सके और आगे से कोई भी गलत कदम उठाने का साहस न कर सके। जो भ्रश्ट कर्मचारी हैं उन्हें इस प्रदे ा में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः अब आप समाप्त करें, आपको बोलते हुए काफी समय हो चुका है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें कह कर समाप्त करूंगा। मेरा आपके द्वारस सरकार को एक सुझाव है कि जो भ्रश्ट काम होते हैं इनको रोकने के लिए हमारी सरकार को बडा संघर्श करना पडेगा और कडे हाथों डील करना पडेगा।

जो गलत काम आज हमारे प्रदे ा में हो रहें हैं, उन से लोगों को राहत मिलेगी और तभी एक गरीब आदमी सुख की सांस लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं इसके लिये सरकार ने कोई लगभग सवा करोड रुपया रखा हैं इस बारे में मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने इलाके उचाना की बात करना चाहता हूं वहां पर 49 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी गांव में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। इन गांवों में खाराा पानी है, सरकार को इन गांवों की तरफ खास ध्यान देना चाहियेय। मेरे इलाके के साथ डिसक्रिमीने ान हो रहा है .....

आवाजें: आपके पिता जी भी मिनिस्टर रहे हैं, उस टाईम आपने कुछ नहीं करवाया।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: उस टाईम जितना हो सकता, हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आज ट्रांसपोर्ट की हालत बिगड रही है, उसकी हालत सुधारने के लिये जय जरूरी है कि पहले सडकों की हातल को सुधारा जाए। आज देखें तो पता चलता है कि नै ानल हाईवेज पर भी कई जगहों पर सडक टूटी पडी है कोई मुरम्मत नहीं हो रही है, जिसके कारण रोडवेज

सर्विस अच्छी नहीं है। रोडवेज घाटे में जा रही है। मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि जो सडकें पिछले साल बनी थी, वे अब इस साल टूट गई हैं इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग का एक सैल बनाया जाए जो कि इस तरफ ध्यान दे और सरकार स्वयं अपनी देख रेख में यह सारा काम करवाये। इस ठेकेदारी सिस्टम को बंद करने पर ही इन कामों में सुधार आ सकता है। मैं अंत में एक बार फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव यहां पर दिये गये हैं, सरकार उनको भीघ्र ही पूरा करे। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(महम): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एप्रोप्रिए ान बिल यहां पर बाबू मूल चन्द जी ने पे ा किया है, उसमें बहुत सा खर्चा तो ऐसा है जो कि सरकार पहले की कर चुकी है और अब सदन से उसकी स्वीकृति लेने के लिये यह बिल पे ा किया गया है। मैं तो समझता हूं कि जो पैसा 1978–79 में खर्च किया गया है और जिन कामों के ऊपर वह पैसा खर्च किया गया है वे बहुत ही अच्छे काम हैं और सचमुच उनकी सराहना की जानी चाहिए थीं इसके साथ साथ हमारी सरकार ने यह एक बड़ा अच्छा काम किया है कि जो नान गवर्नमैंट कालेज थे, उनकी ऐड 35–40 परसैंट से बढाकर 75 परसैंट कर दी है, जिसके लिये मैं अपनी सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं लेकिन जो यह ग्रांट

बढाई गई है उसके बावजूद भी आज ि ाक्षा के अंदर जो सही मायनों में क्रांति आनी चाहिए थी वह दिखाई नहीं देती है हालांकि पैसवा बहुत बढा दिया गया है लेकिन फिर भी वहां के जो ि ाक्षक हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है उसमें मैं समझता हूं कि सुधार की आव यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से दो तीन और सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर कालेजों के अंदर यू0पी0 पैटर्न लागू कर दिया जाए तो उससे 10–15 परसैंट का और बोझा पडेगा। अगर सरकार इस सिस्टम को लागू कर देती है और एडी ानल बोझे को बर्दा त कर लेती है तो यह सारी समस्या हल हो जाएगी लेकिन देखने में यह आया है कि ि ाक्षकों को पिछले 10–15 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, जिस ि ाक्षक को वेतन नहीं मिलेगा वह ि ाक्षा क्या देगा ? अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द यू0पी0 पैटर्न को लागू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम हुआ कि हमारी सरकार प्राईवेट टीचर्ज के लिये सिकोरिटी आफ सर्विस सम्बंधी बिल यहां पर लाना चाहती है अगर यह बात ठीक है तो इसके लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं और अगर सरकार के विचाराधीन इस किस्म की कोई बात नहीं है तो मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि वह इस किस्म का बिल भीघ्र लाए। जब तक ऐसा बिल नहीं लाया जाता है तब तक हमारी ि ाक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। अगर ि ाक्षक को पेट भर खाना नहीं मिलेगा और उसके

रहन सहन का स्तर ठीक नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों को क्या ि ाक्षा देगा, इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस किस्म का बिल इसी सत्र में अव य लाएं। जहां तक प्राईवेट ि ाक्षा संस्थाओं को टेक ओवर करने वाले बिल का सम्बंध है, उसमें केवल कालेजों का ही जिकर है। ि ाक्षा हमें कालेजों से भी मिलती है और स्कूलों से भी मिलती है इसलिये कालेजों के साथ साथ उस बिल में स्कूलों को भी भाामिल करने की तरमीम की जाए क्योंकि आज देखने में यह आता है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि स्कूल न रह कर दुकानों में बदल गये हैं। इसलिये मैं सरकार से फिर अनुरोध करूंगा कि इस एक्ट में तरमीम करके कालेजों की बजाये एजुके ान इंस्टीच्यू ान्ज लिखा जाए। ऐसा करने से जिन ि ाक्षा संस्थाओं में मिस मैनेजमैंट है, इररेगुलैरिटी हैं, वह बहुत हद तक दूर हो जाएगी।

16.00 बजे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैनाल एक्ट के बारे में अपनी सरकार से गुजारि ा करना चाहता हूं। हमारे कैनाल एक्ट के अंदर एक प्रोवीजन है कि जो किसान म्यूनिसिपल कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी के एरिया में आठ किलोमीटर के अंदर अंदर चारा बोता है तो उस पर टेक्स लगेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने पार्टी मीटिंग के अंदर मेरे को इस बारे में गौर करने के लिये कहा था। इस चीज से किसान बहुत बेचैन हैं इसलिये सरकार से मेरी गुजारि ा है कि इसमें फौरी तौर पर अमैंडमैंट की जाए। इसके

अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग वाह ंपर अपनी मोटर या टयूबवझैल लगा कर उन पर प ुओं के चारे का इंतजाम करने के लिये गंडासा लगाते हैं उस गंडासे पर भी सौ रुपये टेक्स लगाया जा रहा है। यह किसान के साथ कितनी ज्यादती है। वीरेन्द्र सिंह जी ने मुझे मालूम हुआ था कि इस पर अभी अभी कोई एक ान लिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करयना चाहता हूं कि अगर अभी एक ान न लिया गया हो तो फौरी तौर पर एक ान लेकर इस टैक्स को भी माफ किया जाए।

आखिरी बात मैं पक्की नालियों के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा सरकार नहरों को, डिस्ट्रीब्यूट्रीज को तथा वाटर कोर्सिज को पक्का करने पर बहुत खर्च कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है इनको पक्का करने से पानी की बचत होती है लेकिन किसान के ऊपर इनका जो खर्चा पडता है वह बहुत अधिक है। अंग्रेजों के वक्त लोगों से जमीन का माल नहीं पाटा करता था और लोग माल देने की बजाये जमीन को छोडना पसन्द करते थे। आज इन नालियों ने किसानों की वही हालत कर रखी है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार जहां किसानों के लिये इतना कुछ कर रही है वहां इन नालियों को पक्का करने का खर्चा भी महकमे के ऊपर डाला जाये। इससे जहां किसान की पैदावार में बढौतरी होती है वहां सरकार के मार्किटिंग बोर्ड को भी आमदनी होती है क्योंकि किसान जितना ज्यादा अनाज बेचेगा उतना ही मार्किटिंग बोर्ड को लाभ होगा।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन सरकार आधे परसैंट पर लेती है वही पैसा आगे जाकर किसान को साढे दस परसैंट पर दिया जाता है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि किसान को को भी यह पैसा आधे परसैंट पर ही दिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो डिमांडज हैं मैं इनके बारे में कुछ बातें कहूंगा। जैसे अभी एक साथी ने बताया कि हरियाणा के अंदर नालियां पक्की की जा रही हैं और किसान इस वजह से बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सिरसा जिले के किसान इसके लिए सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। सरकार इस काम पर आठ आने खर्च करके किसान से डेढ रुपया वसूल करेगी औ।र इस वजह से वसूली के वक्त किसान अपने घर छोड कर भाग रहे हैं। यह ठीक है कि नहरें पक्की बनने से या खाल पक्के बनने से किसानों को फायदा होगा लेकिन इस खर्च की वसूली इतनी अधिक है कि किसान इसको सहन नहीं कर सकता। इसलिये सरकार इस खर्च को खुद सहन करें। दूसरे जो पेसा हमें वर्ल्ड बैंक से मिलता है वह आधे परसैंट सूद पर मिलाता है लेकिन वही पैसा किसान को साढे दस परसैंट पर दिया जाता है इसे भी किसान सहन नहीं कर सकता इसलिये यह पैसा भी किसान को आधे परसैंट पर ही दिया जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो घाटे का बजट

है या घाटे की दुकान है जब तक सरकार इसको ठीक नहीं करेगी तब तक हमारा काम ठीक नहीं चल सकता। इस वक्त हरियाणा के अंदर जितनी भी कोरपोरे ांज हैं, बोर्ड हैं या निगम हैं इन तमाम को तोड दिया जाए और जो हमारे अफसर हैं वह इस काम को करें और महकमे का मिनिस्टर उसकी सुपरवीजन करें तो चेयरमैनों पर लाखों रुपये कारों के कोठियों के और भतों के जो खर्च होते हैं उसकी बचत हो सकती है। मैं कहता हूं कि किसी चेयरमैन की जरूरत नहीं सरकार नइ पर फिजूल खर्च कर रही है। अगर इनको हटा दिया जाए तो हरियाणा सरकार के काम में कोई रूकावट नहीं आएगी। दूसरी मेरी अर्ज यह है कि आज हमारे जो आई0ए0एस0 अफसर हैं या ए ग्रेड के अफसर हैं इनको हम कम रियायत दें। इन पर कारों और कोठियों का बहुत खर्च होता है। इनकी बजाये हमें छोटे दर्जे के कर्मचारियों को जैसे दर्जा दो, तीन और चार कर्मचारी हैं इनको ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से हम इस दे ा के अंदर जो सही रचना देखना चाहते हैं वह हमारे सामने नजर आएगी। इस वक्त मैं देखता हूं कि बंसी लाल के जमाने में जितनी सीनियर अफसर थे वे आज भी हमारी सरकार के अंदर हैं और इन सब की तरक्की हुई है। ये आज मालिक बन कर सरकार को चला रहे हैं चाहे एस0के0 मिश्रा साहब हों चाहे कोई और साहब हों सरकार को चला रहे हैं। हम लोग तो यहां बैठे हैं लेकिन असल मायनों में सरकार वे चला रहे हैं। आज स्टेट में जितने भी आई0जी0 हैं, डी0आई0जी0 हैं और जितने भी बडे अफसर हैं उनमें से 50 प्रति ात अफसर ऐसे हैं

जो बंसी लाल की सरकार के वफादार थे और आज इस सरकार ने उन्हीं की सबसे ज्यादा तरक्की की है। कोई पता नहीं कि उनका रूप रंगा क्या है, अंदर से वे सरकारे को तोडना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि हरियाणा कं अंदर वह अफसर ाही पर कंट्रोल करे। अगर इन पर हमारी असैम्बली ने या हमारे नेताओं ने कंट्रोल न किय तो हमारी जनता पार्टी बदनाम हो जाएगी क्योंकि वे अंदर से चह चाहते हैं कि जनता पार्टी बदनाम हो जाये और बंसी लाल की सरकार फिर से हरियाणा के अंदर कायम हो जाए। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि इन लोगों को प्रोमो ान दी जा रही है और ये लोग हरियाणा में राज कर रहे हैं इस वक्त हरियाण की अंदर जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के सलाहकार बनाये हुए हैं वे दो को छोड कर सब उसी के जमाने के हैं। एक दो तो अंगेजी राज के जमाने के भी हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि इन अफसरों को जो लम्बी कारें दी जाती हैं और हवाई जहाज दिये जाते हैं यह फालतू खर्च हैं मैं चाहूंगा कि इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए कि कोई अफसर ज्यादा खर्च न कर सके। ज्यादा डी0ए0, टी0ए0 न ले और इसी तरह कोई मंत्री भी ज्यादा डी0ए0, टी0ए0 न ले सके।

श्री उपाध्यक्षः आप बिल पर बोलें।

कामरेड भांकर लालः इसके अंदर मैंने सिर्फ स्कूलों के लिये एक बात कहनी है। कुरुक्षेत्र वि वविद्यालय के लिये तो सरकार ने इतना पैसा रखा है परन्तु प्राईमरी स्कूलों पर कोई रुपया खर्च नहीं किया जाता है। इन प्राईमरी स्कूलों से पढकर ही बच्चे इन वि वविद्यालयों में आते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर आसमानकी ओर मुंह उठाये बडे बडे होटल, पर्यटन सैंटर बनाये गये हैं। इन चीजों पर उस वक्त खर्च होना चाहिए था जब हमारा प्रदे ा इतनी तरक्की कर लेता कि हमारे पास इन चीजों के लिये पैसा बचता। हमारे फोर्थ क्लास एम्पलाईज भूखे मर रहे हैं। वे कितने दिनों से धरना दे कर बैठे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी प्रकार गरीब किसान जो बेचारे भूख से मर रहे हैं उन पर यह पैसा खर्च करना चाहिए था। सबसे पहले जो आसमान पर बैठे हैं उनका नीचे लाना है और जो जमीन पर बैठे हैं उनको ऊपर लाना है।

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिये।

कामरेड भांकर लालः एक और बात के अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि बडा अच्छा बजट बनाया है। यह बजट तो ड्रामा है। चौधरी देवी लाल के कहने पर बना दिया और फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बजट पे ा कर दिया। अब बीचव में अपने ही लोगों द्वारा जैसे औम प्रका ा जी हैं, से कहलवाते हैं कि बजट खराब है ताकि मूल चन्द जैन इस्तीफा दे दें। एम0एल0एज0 की एक कमेटी इसलिये बना दी है कि बजट में

जो टैक्स लगाये हैं उन पर दोबारा विचार करें। यह अच्छी बात है लेकिन इस बजट में जो भी पैसा रखा गया है वह ठीक ढंग से खर्च होना चाहिए। सारा पैसा पानी के हिसाब से, सडकों के हिसाब से, स्कूलों के हिसाब से सभी क्षेत्रों में बराबर खर्च होना चाहिए। अगर समाजवाद लाना है तो जो भी पैसा खर्च करना है वह ठीक ढंग से खर्च होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः भांकर लाल जी आप बैठियें

कामरेड भांकर लालः आजकल लोगों की हालत बहुत खराब है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि भूमिहीनों को, मुजारो को, बडे जागीरदारों को जमीनें बांटी जायें। अगर हम सही मायनों में जनता पार्टी की सरकार को कामयाब करना चाहते हैं तो जय प्रका ा और लोहिया के सिद्धान्तों पर चलें।

श्री उपाध्यक्षः आप बेठिये

कामरेड भांकर लालः इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं।

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने जिन बातों का जिक्र किया है, मैं उनको दोहराऊगा नहीं। इन एप्रोप्रिए ान बिल में, पिछले डेढ दो सालों से जब से जनता सरकार बनी है भिन्न भिन्न ..... (विघ्न)

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। ये कौन सी मांग पर बोल रहे हैं। इन्होंने डिमांड नम्बर तो बताया नहीं है।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार की पिछले दो सालों में इस हाउस में या पब्लिक में जो नुक्ताचीनी हुई है उससे यह उम्मीद की जा सकती कि सरकार उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहरायेगी। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि जो 35–36 करोड रुपये की डिमांडज हैं इससे यह जाहिर नहीं होता है कि सरकार की नीति मजदूर को ऊपर उठाने की है। इन अनुपूरक मांगों में मन्त्रियों को जो डिस्क्रि ानरी ग्रांटस सरकार ने दी है वह 10 लाख 97 हजार रुपये की है। इसको बढ़ाने की वजह ये बताई गई है कि पिछले दिनों मंत्रियों की संख्या बढ गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा दो तीन मंत्रियों की गिनती बढ है लेकिन इनके बढने से 11 लाख की डिस्क्रि ानरी ग्रांट बढ गई जो कि बहुत ज्यादा है। मंत्रियों को चाहिए कि इस वैल्यूएबल पैसे की लोगों की भलाई के लिये प्रयोग करें। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के कहने और करने में बडा भारी वाईड गैप जाहिर होता है। पब्लिक सविर्स कमी ान के लिए भी 1 लाख 96 हजार रुपया अनुपूरक मांगों में दिया गया है और इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्टस पुलिस के लिए 59 लाख 76 हजार रुपए देने का प्रबन्ध किया गया है। यह पैसा बहुत ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने और मेरे साथियों ने कही हैं

उनसे सिद्ध होता है कि गवर्नमैंट क्या कारगुजारी कर रही है। सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट की डिमांड नंबर 13 में ओल्ड ऐज पैं ान के लिये 5 लाख रुपये की रकम रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह जो बूढे व्यक्तियों की पैं ान 25 रुपये और 50 रुपये की थी यह कांग्रेस सरकार ने जाने से पहले सन 1977 के चौथे महीने में की थी। यह उसके लिये मांग रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सो ाल वैलफेयर के दफतर की बात आप से बताना चाहता हूं कि वहां की कार्यप्रणाली कितनी बुरी हालत मैं हैं अगर एक फार्म नीचे से वैरीफाई होने के बाद यहां ऊपिर आता है तो उसके प्रासैस का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आज से अढाई तीन साल पहले हमारे भाहर की एक गरीब विधवा औरत जो 65 साल की थी और जिसका कोई सहारा नीं था, उसकी दरखारूत को ले जाने को मौका मुझे मिला। तीन साल से उसे आज तक कोई पैं ान नहीं मिली है। कई बार वह फार्म ऊपर से नीचे के दफतरों में आया परन्तु उस पर कोई एक ान नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्कीम देखने और कहने में तो अच्छी लगती है परन्तु सही ढंग से इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। जिनको कोई सहारा नहीं है, डैस्टीच्यूट हैं, सरकार तो उनको पैं ान देना चाहती है लेकिन सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट वाले किसी की पैं ान आसानी से सैंक ान नहीं करते। अगर किसी की पैं ान करते हैं तो उस गरीब को काफी एडवासं पैसा रि वत के रूप में देना पड़ता है। तब जाकर उसकी पैं ान मंजूर होती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये

जो गरीब आदमी हैं जिनको 25–30 रुपये पैं ान के देने का प्रावधान सरकार करती है तो उनको यह रा ि ा सही ढंग से नहीं मिलती है।

दूसरी तरफ उपाध्यक्ष महोदय, 1 करोड 41 लाख रुपये लाटरीज के रखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी कौन खरीदते हैं ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाज का सबसे पिछडा तबका है जिनको अपने उपर आत्म वि वास नहीं होता है जो यह समझते हैं कि लाटरी के पेसे से भाायद उनकी किस्मत बदल जाये, वही लोग लाटरी की टिकट खरीदते हैं। भगवान की कृपा से अगर उनकी लाटरी निकल आए तो उनके अच्छे दिन आ जउएं यह सरकार अपने अपको वैलफेयर करने वाली सरकार कहती है परन्तु मैं आपको बताता हूं कि एक साल के अंदर लाटरी के जरिए जो एक डेढ करोड रुपया आता है वह गरीबों की जेब से ही आता है। इसमें से कुछ पैसा तो एजेंटो की जेब में चला जाता है और कुछ इ ि तहार वगैरह पर खर्च हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह उन गरीब आदमियों का बडा भारी भाोशण है जिनको सरकार दूसरी तरफ कर्जा देने का क्लेम करती है। इसके साथ ही जुडती बात मैं और कहूंगा कि हरियाणा में सारे साल में जनवरी से लेकर दिसम्बर तक रैडक्रास के मेले के नाम से हर छोटे बडे कस्बे में मेल लगते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, रैडक्रास सोसाइटी के प्रधान हैं जब कभी मेला लगता है तो कुछ लोग 10–20 हजार रुपया रैडक्रास सोसायटी को दे देते हें लेकिन यह

नहीं पता कि आगे कितने का कन्ट्रैक्ट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, उस मेंले में सरासर जुआ चलता है। उस रैडक्रास मेले में सिवाय जुआखारी के और कोई दूसरी बात नहीं है। ऐसे मैले में बडे अफसोसनाक नाच, गन्दे नाच तथा स्त्रियों का नग्न प्रद ान करके गरीब आदमियों को वहां खींचा जाता है और उन गरीब आदमियों का जुए और लाटरी के जरिए करोडो रुपया सरकार के खजाने में चला जाता है। रैडक्रास सोसाइटी एक बहुत ऊंची चीज है। इसका उद्दे य यह है कि गरीब आदमियों को दवाई दारू और हर तरह की मदद दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही काम होंगे तो मैं सरकार से यह विनती करता हूं कि वह रैडक्रास को मुकम्मल तौर से वाइंड अप कर दें। गरीब आदमियों को इस तरह की मदद की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे गरीब आदमियें का ही करोडों रुपया गन्दे गाने सुना कर, गन्दे नाच दिखा कर और जुआ खिला कर लूटा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि एप्रोप्रिए ान बिल में डिमांड नंबर 4 जो है वह रैवेन्यू डिपार्टमैंअ से ताल्लुक रखती है। इसमें जुडि ायल और नान जुडि ायल स्टैम्पस के लिये 1 लाखा 88 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह उन गरीबों का भाोशण करने की तीसरी मांग है जिनके बारे में अभी मैंने दो तीन उदाहरण दिए हैं एक ओर सरकार वैलफेयर स्टेट हाने के नाते यह बात बार बार बडे जोर से कहती है कि सरकार इस सारी लिटिगे ान को फ्री करना चाहती हैं खासतौर से गरीब आदमियों

के लिये और दरमियानो तबके के लिये लेकिन दूसरी तरफ स्टैम्प डयूटी ..... (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, स्टैम्पस के लिये तो 2 लाख 26 हजार रुपया मांगा है।

श्री भाम ोर सिंहः जैन साहब देखिए यह पेज 12 पर 1 लाख 88 हजार रुपया जो है वह आपने इस बात के लिये मांगा है कि जुडि ियल और नान जुडि ियल स्टैम्पस खरीदने हैं। इसमें जो लिटिगे ान है, खासतौर से फौजदारी की और छोटे मोटे दीवानी मुकद्दमों की उसमें निहायत गरीब आदमी ही छोटी कचहरियों और कोर्टस में जाते हैं सरकार भाायद इस बात का प्रयत्न करती है कि वह गरीब लोगों को फ्री लीगल एड देगी मगर दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिल सकती। मेरा भी इस लाईन का 15–16 साल का तजुर्बा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल एक मिथ्या और झूठी बात है। अगर सरकार उन गरीब आदमियों की ठोस मदद करना चाहती है तो उसका सीधा तरीका सरकार के हाथ में यह है कि कम से कम ऐसे तबके के लिये, गरीब आदमियों के लिए और नीची कैटेगरी के जो लोग हैं या जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं उनके लिये यह जुडि ियल और नान जुडि ियल स्टैम्पस जो भी है, उन्हें मुफ्त प्रदान करें।

इसके अलावा मंत्रियों के लिए एक साल में दो दो बार रुपये की मांग करने से जाहिर होता है कि पहले भी यह मांग की

गई होगी। दूसरी बात जो मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा वह है रैवेन्यू डिपार्टमैंअ की डिमान्ड नम्बर चार उसमे रिलीफ आन अकाउन्ट आफ नैचुरल क्लाइमिटीज के लिये पैसा मांगा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में जैसा कि आपको ज्ञात है भाायद कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां ओले न पडें हों और सरकार ने इस बात का हाउस में वचन दिया और रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने पालिसी का एलान भी किया है कि सारे हरियाणा में जहां भी ओले से नुकसान हुआ है वहां तकावी के रूप में सबसिडी के रूप में और भिन्न भिन्न तरीकों से ग्रांट देंगें। उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया है कि इसी महीने मार्च में जो ओले पडे हैं उनकी वजह से हुए नुक्सान के लिये भी रिलीफ दी जाएगी ? उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी और फरवरी में भी ओले पडे। लेकिन ऐसी भी बहुत से इलाके हैं जहां इतनी अधिक मात्रा में ओले नहीं पडे हैं। परन्तु कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे मेरे हल्के नरवाना सब डिविजन के 12 गांवों में जिनमें 5–6 गांव हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर साहब के हैं वहां 16 फरवरी को इतने भारी ओले पडे हैं कि मैं उनकी एक बोरी भर करके सैक्रेटेरिएट में मंत्रियों को और दूसरे लोगों को दिखाने के लिए लाया था और साथ ही फसल के नमूने भी ले करके आया था। पिछले सौ सालों में कभी ऐसे ओले नहीं पडे इसलिये उन इलाकें में सब किसानों को समान रूप से सहूलियतें दी जाएं। सरकार से मेरी यही दरखास्त है।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय समाप्त हो गया हैं

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। डिमांड नम्बर 10 पब्लिक हैल्थ की है। उसमें वाटर सप्लाई स्कीम का जिक्र किया गया है। नरवाना में जो वाटर सप्लाई स्कीम है उस पर 30–40 लाख रुपये खर्च हुए थे लेकिन 10–15 दिन पहले वह सारी स्कीम क्लैपस हो गई। उसके जो टैंक और वैल थे वे नीचे बैठ गए। वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एस0डी0ओ0 (सिविल) हैं उन्हौंने पब्लिक हैल्थ के एस0डी0ओ0 से इस बात की दरख्वास्त की है कि हमारे पास टैक्नीकल नो हाऊ नहीं हैं इसलिये मेहरबानी करके आप इस स्कीम को टेक औवर कर लें। इसकी मैंटीनैंस और रिपेयर का खर्चा म्यूनिसिपल कमेटी देने के लिये तैयार है। मैंने भी जींद जा करके उनसे कहा कि भाहर में पीने के पानी का सिस्टम खत्म हो चुका है जिसके कारण कोई खतरनाक बीमारी फैल सकती है इसलिये आप इसको टेक ओवर कर लें लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि यदि सरकार कहेगी तो हम टेक ओवर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का जो एटीच्यूड है उसके लिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से और सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसी बात जो कि सब के नोटिस मकें है उस पर फौरन एक ान लिया जाए। इसी तरह से डिमांड नम्बर 11 में 5 लाख रुपये मांगे गये हैं, वह अम्बाला की म्यूनिसिपल कमेटी को सहातय देने के लिये हैं। पिछले साल उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में अर्बन डिवैलपमैंट एरिया के लिये मांग आई थी उसकी अमाउंट तो मुझे ठीक याद नहीं है भाायद 15–15 लाख रुपये रोहतक और सिरसा

की दो म्यूनिसिपल कमेटियों को दिया गया था। उसके बारे में हाउस के सारे मैम्बरों ने बडी भारी नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि हरियाणा में कोई भी ऐसा नगर या भाहर नहीं है जिसमें पक्की नालियों, पकी गलियां, नीने के पानी की और बिजली की हालत अच्छी हो। इसलिये इन दोनों भाहरों को क्यों पैसा दिया जा रहा है ? सरकार मुंह देख करके टीका लगाती है कि कौन कौन से भाहरों को पैसा देना है। सरकार को चाहिए कि वह प्रायरिटी फिक्स करै। सरकार पहले सलम्ज एरिया को ले फिर गलियों को पक्की कराये उसके बाद पीने के पानी और बिजली आदि का प्रबन्ध करे इस तरह से प्रायरिटी सरकार को बनानी चाहिए लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और उन्होंने एक ही भाहर को यह कह करके कि उसमें डिवैल्पमैंट का काम रूका हुआ है उसको 5 लाख दे दिए हैं यह बात ठीक नहीं है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग सं0 1, 7, 13 तथा 17 के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मांग नं0 1 पर अपने विचार रखूंगा। जब मैं इस मांग पर दृश्टिपात करता हूं तो मुझे ऐसा खर्चा दिखाई देता है जिसका औचित्य समझना मेरी समझ से बाहर है। इसमें लिखा है कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर यह खर्चा हुआ है जबकि आप हमारे सामने हट्टे कट्टे बैठे हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य को

देखते हुए हमें आपसे प्रेरणा मिलती है कि आप जैसा स्वास्थ्य हमारा भी होना चाहिए। लेकिन इस डिमांड के मुताबिक आपके स्वास्थ्य पर 10900 रुपये का खर्च दिखाया गया है।

श्री मूल चन्द जैनः 36करोड रुपये की डिमांड हाउस के सामने हैं और आप दस दस हजार रुपये की बात करते हैं।

स्वामी अग्निवे ाः जी हां, यह तो मांग सं0 1 में दिया हुआ है। हमने पिछले डेढ दो साल से कभी बीमार पडतु हुए नहीं देखा लेकिन यह समझ नहीं आता कि इनता पैसा आपके स्वास्थय पर कैसे खर्च हो गया। इसकी जांच हो जानी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि विभाग वालो ंने आपके साथ हेराफेरी की है।

इसके अतिरिक्त इसी डिमांड की आइटमक नंबर 2 में 652350 रुपया एम0एल0एज0 की टूरिंग के लिये रखा गया है। एम0एल0एज0 को इधर उधर मूव करना पडता है इसलिये टूरिंग इन्टैंसिव हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अनुभव करता हूं कि एम0एल0एज0 को टूर करने के लिये अपनी कांस्टीच्युएंसी से चण्डीगढ आने या इधर उधर जाने के लिय रेल के फ्री कूपन मिले हुए हैं जिनके तहत एक एम0एल0एज0 साल में 16000 किलोमीटर तक सरकारी की तरफ से जनता के पैसे के ऊपर भारत में कहीं भी टूर कर सकता है सरकार ने एम0एल0एज0 को अधिकर दिया है कि जाओ, यह कूपन ले लो, तुम फस्ट क्लास ट्रेन में यात्रा कर सकते हो और साथ में एक और व्यक्ति ले जा

सकते हो। जब गवर्नमैंट ने इनको यह सुविधा दे रखी है कि 16000 किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास में फ्री यात्रा कर सकते हो तो 6 लाख रुपया एम0एल0एज0 को टूरिंग के लिये क्यों स्वीकार करवा रहे हैं ? यह बात हमारी समझ से बाहर है। बस में यात्रा करना हमारे लिये फ्री है, रेल में यात्रा करना फ्री है तो टी0ए0, डी0ए0 क्लेम करने का क्या औचित्य है ? यह एक गम्भीर मामला है, इस पर विचार करना आव यक है। अगर किसी एम0एल0ए0 को सरकार कुछ देना चाहती है तो दे क्योंकि कई बार राजनैतिक परिस्थितियों में मजबूरी भी हो सकती है लेकिन जिस ढंग से आप देते हैं यह उतच नहीं। एक तरफ तो हम जनता को बताते हैं कि हमने कोई अनुचित काम नहीं किया। अपने विधायकौं के लिये फ्री ट्रैवलिंग कर दिया, बसों और रेल में फ्री ट्रैवलिंग कर दिया इसके बाद किसी एम0एल0ए0 द्वारा टी0ए0, डी0ए0 क्लेम करने का औचित्य कहां रह जाता है ? जिन कानूनों के तहत टी0ए0, डी0ए0 दिया जाता है ये कांग्रेस भाासन काल के बने हुए हैं। क्या आप इन्हीं कानूनों को रखना चाहते हैं ? ये कानून जनता भाासन काल में बदलने चाहिए। अगर बसों में यात्रा करने पर बाकायदा किराया लिया जाए, रेल में यात्रा करने पर रेल का भाड़ालिया जाए, फिर टी0ए0, डी0ए0 क्लेम करने का औचित्य है, अगर फ्री ट्रैवलिंग है तो कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, एक एम0एल0ए0 हिसार में बस में बैठ कर उसी चण्डीगढ में पहंच जाता है। आप इस बात की जांच करवा लें, जितने एम0एल0एज0 मेरे साथ आते हैं, वे सब के सब चण्डीगढ में मीटिंग अटैंड करने

के लिये बसों से आते हैं लेकिन जब टी0ए0 का बिल बनता है, ये रेल का फर्स्ट क्लास किराया चार्ज करते हैं यानि डयोढा किराया चार्ज किया जाता है। आते तो बस से हैं और वह भी फ्री ट्रैवल करते हैं लेकिन चार्ज करते हैं रेल का किराया और वह भी डयोढा। जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझ सकती लेकिन जनता समझ गई हैं और इन जनता के नुमांयदों को जनता कभी मुआफ नहीं करेगी, यह गम्भीर चीज है .....

श्री उपाध्यक्षः पहली बात जो आपने डिप्टी स्पीकर साहब, के मैडिकल बिल्ज के बारे में कही, मैं इसको क्लीयर कर देता हूं। इस डिमांड में लिखा है –

"This expenditure is required to discharge the pending liabilities of outstaning medical bills etc. of Ex Speakers/Deputy Speakers ..... ?

यह रा ि मेरे से ताल्लुक नहीं रखती और न ही मेरे पर लागू होती है। क्योंकि इसमें लिखा है "एक्स डिप्टी स्पीकर"।

स्वामी अग्निवे ः डिप्टी स्पीकर साहब, तो आप भी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह चीज पहले वाले डिप्टी स्पीकर साहब, पर लागू होतीी है।

स्वामी अग्निवे ः ठीक है जी। हां तो मैं कह रहा था कि आप व्यक्तित्व रूचि लेकर टी0ए0 रूलज को बदलवाएं। यात्रा

भत्ता किस आधार पर क्लेम किया जाता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती मैं लगभग डेढ साल से समझने की कोि ा ा कर रहा हूं कि जब ट्रैवलिंग फ्री है लेकिन फिर यात्रा भत्ता लेने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्षः क्या आप किसी कमेटी के मैम्बर नहीं हैं ?

स्वामी अग्निवे ाः मैं किसी कमेटी का मैंबर नहीं हूं और न ही मैंने कभी टी0ए0, डी0ए0 लिया है। हाउस अटैंड करने के लिये आता हूं लेकिन कभी टी0ए0, डी0ए0 क्लेम नहीं किया। मैं एजुके ान बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूं लेकिन कभी टी0ए0,डी0ए0 नहीं लिया। हमारा हक ही नहीं बनता क्योंकि जब हम जनता के पैसे पर फ्री यात्रा कर सकते हैं तो किस आधार पर टी0ए0, डी0ए0 क्लेम कर सकते हैं ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जहां लेना चाहिए वहां ले लेकिन जनता की सेवा करने के लिए जब यात्रा मुफ्त कर दी हो तो यात्रा भत्ता लेने का क्या औचित्य है, आखिर कोई न कोई हेतु तो होना चाहिए। आ ाा है जैन साहब मेरे इस सवाल का उत्तर देंगे और स्पश्टीकरण देंगे कि किस आधार पर टी0ए0, डी0ए0 दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एम0एल0एज0 चण्डीगढ़ में मीटिंग अडैंट करने के लिये आते हैं और मीटिंग मु कल से कई बार आधा घंटा चलती है। अपनी कांस्टीच्यूएंसी से चलकर एक एम0एल0ए0 लगभग उसी तदन चण्डीगढ़ में पहुंच जाता है दूसरे

हरियाणा प्रान्त इतना लंबा चौडा भी नहीं है कि यू0पी0 की तरह मीटिंग अटैंड करने के लिए तीन दिन पहले चलना पड़ता हो। हरियाणा के एम0एल0ए0 एक दिन में चण्डीगढ़ में पहुंच जाते हैं, लेकिन टी0ए0 तीन दिन का क्लेम करते हैं एक दिन मीटिंग के पहले दिन का टी0ए0, एक दिन मीटिंग वाले दिन का और एक दिन मीटिग अटैंड करके वापिस जाने वाले दिन का यानी तीन दिन का टी0ए0 क्लेम करते हैं इसके अतिरिक्त तीन दिन का डेली भी लिया जाता है। एक तरफ तो हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के घटिया कार्य करते हैं बातें तो हम कर रहे हैं बडी बडी लेकिन आचरण और व्यवहार में कुछ नहीं प्रतीत होता। हमे चाहते हैं कि जितना धन बटोर सकें, बटोर लिया जाए, यह आचरण ठीक नहीं है। मैं जैन साहब से आ ाा रखता हूं कि मेरी इन सारी बातों का उत्तर देंगे और अनुचित ढंग से जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर अंकु ा रखने की कोि ा ा करेंगे।

एक दो बातें और वि ोश रूप से कहना चाहता हूं। मांग सं0 7 की आइटम सं0 7 में एम0एल0ए0 होस्टल की कैंटीन को चलाने के लिये 48000 रुपये एडी ानल खर्चे के लिए मांगे हैं। हम होस्टल में खाना खाते हैं और पैसे देते हैं लेकिन उस पैसे से होस्टल का खर्च पूरा नहीं होता है। अगर पूरा नहीं होता तो खाने की कीमत बढा दीजिए और नो प्रौफिट नौ लौस के बेसिज पर कैंटी का चलायें। सरकार ने 48000 रुपया किस लिये

दिया है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने हरियाणा भवन को मैंटेन करने के लिये 6 लाख रुपया देकर उसको सबसिडाई किया है। अब उसमें कौन लोग ठहरते हैं ? गरीब किसान नहीं ठहरता, मजदूर नहीं ठहरता अगर ठहरते हैं तो बडे बडे आफिसर, सैक्रेटरी, कमि वर, मिनिस्टिर और एम0एल0एज0। गरीब आदमी हरियाणा भवन में नहीं ठहर सकता। ये बडे बडे लोग ठहरते हैं और इनसे 2 रुपये फी कमरा डेली का किराया लिया जाता है और इसके मुकाबले में अगर आप होटल के कमरों का किराया देंखें तो 150 या 200 रुपये एक दिन का किराया लिया जाता है। मैं यह नहीं चाहता कि 2 रुपये या 5 रुपये की बजाय 15 या 20 रुपये प्रति कमरा प्रति दिन का किराया होना चाहिए। हरियाणा भवन पर जो खर्चा आता है वह कैंटीन से और रैंट से वसूल होना चाहिए लेकिन इस प्रकार पैसे देकर फजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए और जनता की भलाई के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना चाहिए ताकि कम से कम टैक्स लगा सकें और जो लोग आज तक मौज करते रहे हैं उन पर अंकु ा रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भाम ोर सिंह जी ने बडी अच्छी बात कही कि लाटरी एक जुआ है, और रैडक्रास के बारे में जो कुछ कहा उससे मैं भी सहमत हूं लेकिन चौधरी भाम ोर सिंह जी को यह कहना चाहिए कि जुआ और रैडक्रास को भाुरू करने

वाले वे ही हैं, वहीं दोशी हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लाटरी का सिस्टम कांग्रेस सरकार ने ही भुरू किया था .....

श्री भाम ेर सिंहः आप बंद करवा दो।

स्वामी अग्निवे ाः बंद करवाने की मांग का तो मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आपको यह समझ होनी चाहिए कि यह पाप किसने किया है ? जुआ खिलाने का कार्य किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है और अब जनता पार्टी से यह अपेक्षा रखते हैं कि इसको बंद करवाया जाए खुद को देवता बताते हैं और जनता पाट्री को कहत हैं कि यह जुआ खिलवा रही है। रैडक्रास में गन्दे नाच नचवा रही हैं ठीक है मुझे भी रिपोर्ट मिली है कि वहां पर गंदे नाच होते हैं।

श्री उपाध्यक्षः अ ाोका होटल में तो आप गये थे।

स्वामी अग्निवे ाः अ ाोका होटल में तो मैं गरीबों को लेकर गया था यह दिखाने के लिये कि फाईव स्टार होटल्ज का क्या कल्चर है, कितनी वाहीयात बातें वहां होती हैं। वहां एक कमरे का एक रात का किराया पन्द्रह सौ रुपये है। यह भी केवल ठहरने का है, भोजन इसमें भाामिल नहीं है। अब आप बताएं कि कोन गरीब वहां ठहतरा होगा ? केवल ब्लैक मनी पर पलने वाले लोग ही वहां ठहरते हैं।

श्री उपाध्यक्षः वहां फौरेन डिगनिटरीज ठहरती हैं।

स्वामी अग्निवे I: हमारे दे ा के लोग भी वहां ठहरते हैं। आप जानते हैं कि समानान्तर अर्थ व्यवसाि हमारे यहां काले धन की है। ऐसे धन वाले लोग भी वहां ठहरते हैं । (विघ्न)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि लाटरी सिस्टम जो सरकार ने चला रखा है यह एक किस्म का जुआ है। दूसरे जुए को जब सरकार प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है तो यह सरकारी जुआ भी बंद होना चाहिए। इसको बंद करने के लिये एक और कारण भी है। केवल 141 लाख रुपये की यह लाटरी है। इसके टिकटों को छपवाने और बिकवाने आदि पर 120 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं बाकी 21 लाख रुपये के लिए हम सारे हरियाणा की एक करोड इक्कीस लाख जनता को हम जुआरी बनाएं यह कोई औचित्य नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस जुए को बंद कर देती है तो आज हमारे प्रान्त के जो भाग्यवादी लोग हैं वे अपने हाथों से अपनी किस्मत बदलने का संकल्प लेंगे। इसलिए वित्त मंत्री महोदय जी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह लाटरी सिस्टम हरियाणा में अविलम्ब बंद होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ि ाक्षा मंत्री जी ने एक बहुत बडा मजाक किया है। मैं तो समझता था कि वे समाजवादी विचार के हैं और गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कै कैम्पस को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि भाायद यह पैरिस की कोई यूनिवर्सिटी है या न्यूयार्क कीह कोई यूनिवर्सिटी है। बड़ी सुन्दर बिल्डिंग, बाग बगीचे और

औडिटोरियम आदि वहां बने हुए हैं। उसको ओर सुन्दर बनाने के लिए चालीस लाख रुपया दिया जा रहा है। अब आप देखें कि एक तरफ तो केवल एक यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बडी रा ि ा दी जा रही है लेकिन दूसर ि तरफ सारे हरियाणा के प्राईमरी स्कूल्ज, मिडल स्कूल्ज, हाई स्कूल्ज और हायर सैकेण्डरी स्कूल्ज के लिए जो टूटे हुए हैं, जिनकी छतें टपक रही है, केवल मात्र 20 लाख रुपये दिए जा रहें हैं। कोई तो प्राथमिकता का दृश्टिकोण होना चाहिए। हमारी केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट, तारकुंडे कमी ान की रिपोर्ट बताती हें कि स्कूल के सौ बच्चों में से केवल एब बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है। ऐसे बच्चों के लिए और उनकी बिल्डि।ग के लिए जो कि पहले बनी हुई है। 40 लाख रुपया दिया जाना और सारे हरियाणा के स्कूल्ज की बिल्डिंग की मुरम्मत आदि के लिए केवल बीस लाख रुपया दिया जाना उपाध्यक्ष महोदय, यह द ार्ाता है कि यह व्यव करने का अनुचित ढंग हैं यूनिवर्सिटीज के लिए तो पांच साल तह इस तरह से कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। (विघ्न) रोहतक यूनिवर्सिटी के लिए चार करोड रुपये देने जा रहे हैं यह बिल्कुल अपव्यय है। इसकी कोई जरूरत नहीं हैं इसको तो केवल ऐग्जामिने ान यूनिवर्सिटी बनाया जाए। सारे ऐफिलिऐटिड कालेजित के बच्चे यहां आए और एक दो कमरों में परीक्षा देकर के चले जाए। मेरे विचारानुसार तो यह व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। यह बंद किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि यह वर्श अन्र्राश्ट्रीय बाल वर्श के रूप में बनाया जाएगा। इतनी बडी घोशणा यू0एन0ओन ने की है औंर सारे वि व में इसकी चर्चा है। आप यह भी जानते हैं कि ये बच्चें हमारे आने वाले नेता हैं, राश्ट्र की धारोहर हैं और इनको ऊंचा उठाने के लिए इस अन्र्राश्ट्रीय काल वर्श कै अन्तर्गत लाख करोडों रुपयें खर्च करने का विचार है लेकिन हमारे यहां इन गरीब बच्चों के लिए केवल मात्र एक लाख रुपया रखा गया है। अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श का इससे ज्यादा मजाक कोई दूसरा नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, गांव के गरीब बच्चों के लिए जो गांव में गोबर थापते हैं उपले थापते हैं होटलों के अंदर प्लेटें धोते हैं, दूसरों के बच्चों के कपडे धाते हैं, एक बहुत बडी योजना इस सरकार को बनानी चाहिए थी लेकिन उनके लिए केवल एक लाख रुपया का प्रावधान इस ऐप्रोप्रिए ान बिल में किया गया है। मुझे तो भय है कि यह एक लाख रुपया भी उन गरीब बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। बडे बडे जो लोग हैं उनके बच्चों का ही कोई कंपटी ान हो जाएगा, कोई भाो हो जाएगा और एक लाख रुपया भी उन्हीं के ऊनर बहा दिया जाएगा। (विघ्न) तो गरीब बच्चों के लिए इस अन्र्राश्ट्रीय बाल वर्श में एक भी चील इस बिल के अंदर मुझे दिखई नहीं पडी। बडा दुर्भाग्य है जैने साहब के आने के बाद ऐसा होगा मुझे इस बात की उम्मी नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अंदर ि ाडयूल्ड कास्टस के लिए कुछ बातें कही गई हैं लेकिन मैं जैन साहब से निवेदन करता हूं कि वे पूरी सच्चाई के साथ सदन को आंकडें दे कि पिछले 32 सालों में इस दे ा के अंदर हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वे ान की जो बात कही गई उसके तहत पिछली सरकार ने और इस सरकार ने क्या कुछ किया है। हमारे यहां तो चेयरमैन ि ाडयूल्ड कास्ट एवं ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज कमेटी अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 20 प्रति ात रिजर्वे ान के विरूद्ध ए क्लस की नौकरियों में 2.5 प्रति ात लोगों कों नौकरी मिली है, बी क्लास में 2.3 प्रति ात लोगों को नौकरी मिली है और यही हाल सी क्लास की नौकरियों में है। इसके अंदर भी 20 प्रति ात लोगों को नौकरी नहीं मिली है। क्लर्के आदि ग्रेड की जो पोस्टस होती हैं उनके ऊपर भी केवल साढे बारह प्रति ात लोगों को नौकरी मिली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फोर्थ क्लास की पोस्टस के लिए मजबूर होकर बीस प्रति ात रिजर्वे ान इनको देनी पडी है क्योंकि इन पदों पर गंदगी साफ के करने के लिए, कूडा कर्कट उठाने के लिए लोग चाहिएं, वरना भाायद इन पोस्टस के ऊपर भी हरिजनों को आगे नहीं आने दिया जाता। संविधान में हमने लिख रखा है कि हरिजनों के लिए 20 परसैंट का कोटा सर्विसिज में रिजर्व होगा लेकिन वह कोटा काहं मिल रहा है और किसको मिल रहा है ?

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ओल्ड ऐज पैं ान की तरफ दिलाना चाहूंगा। एम0एल0एज0 को तीन सौ रुपये कम से कम पैं ान लेंगे।(विघ्न) एक दिन के लिए भी यदि कोई एम0एल0ए0 बन जाए एक दिन के लिए भी यदि कोई व्यक्ति आपकी बगल में खडा होकर एम0एल0ए0 की भापथ ले ले तो वह सारी जिन्दगी के लिए तीन सौं रुपये से पांच सौ रुपये तक की पैं ान का हकदार हो जाएगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह तो यह बात है लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी जो किसान है, मजदूर है,जिसने अपनी हड्डियां गलाई हैं, खून बहाया है अन्न पैदा करने में और सडकें आदि बनाने में उसको 60–65 साल की उमर में कितनी पैं ान दी जाएगी यह देखने वाली बात है। उसकी पैं ान को 15 रुपये से 25 पैसे बढाकर 25 रुपये 50 पैसे किया गया है। कितनी बडी दया है कि साढे पच्चीस रुपया महीना पैं ान एक आदमी को दी जाएगी ? आज साढे पच्चीस रुपयें कया बनता है यह सोचने की बात है। मेरे तो यह बात समझ में नहीं आती कि एक एम0एल0ए0 को तो कम से कम तीन सौ रुपया महीना पैं ान दी जाए और एक किसान को जिसमें 60–65 साल दे ा की सेवा की है उसको केवल साढे पच्चीस रुपये महीना पैं ान दी जाए लेकिन वित्त मंत्री जी चूंकि मेरे से कहीं ज्यादा समझदार हैं इसलिए वे इस बात को देख लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिए चौपाल बनाने की बात भी इस बिल में आई है। इसके बारे में भी एक बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर बहुत सी जगह लोग चौपाल बनाने के इच्छुक हैं लेकिन ईंटों की बडी दिक्कत है। आज 250 रुपये प्रति हजार के हिसाब से ईंटें मिल रही है लेकिन सरपंच को 150 रुपये प्रति हजार के हिसाब से रसीद दी जा रही है। बाकी के सौ रुपये का हिसाब किताब सरपंच कैसे रखें, इसमें बडी परे ाानी हो रही हें इसका सरकार की ओर से कोई न कोई इंतजाम होना चाहिए। हरिजनों के लिए चौपालें बनाए जाने की एक बडी अच्छी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोची है। लेकिन यह सारी की सारी योजना कागजों पर ही रह जाएगी यदि हम ईंटों का इंतजाम नहीं कर पाए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि वे चौपालें सब बिरादरी के लोगों के लिए बननी चाहिएं। इसी प्रकार से सीमेंट की भी बडी किल्लत चल रही है जिससे लोगों को काफी कठिनाई है (विघ्न) हम तो इन मांगों के विशय में सुझाव ही दे सकते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं हैं भाशण देने का अधिकार अव य है लेकिन इस पैसे में कटौती करने का अधिकार हमारा नहीं है। तेा मेरा निवेदन है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर सरकार अव य ध्यान देगी।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिए ान बिल पर बहस हुई है। मेरा ख्याल था कि इस पर

कुछ रचनात्मक सुझाव आयेंगे क्योंकि अनुपूरक मांगों पर तो बहस पहले ही हो चुकी थी और उनके ऊपर मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। ऐप्रोप्रिए ान बिल के बारे में मैं उम्मीद करता था कि कुछ सदस्यों की ओर से सुझाव आयेंगे और उनसे प्रान्त को कुछ लाभ होगा लेकिन मुझे अफसोस है कि बार बार वही बातें यहां पर रिपीट की जा रही हैं, कोई भ्झी कंसट्रक्अिव सुझाव नहीं आया। जब इन अनुपूरक मांगौं पर बहस हुई उस समय मैंने हाउस में बताया था कि यह 36 करोड रुपया कहां कहां पर खर्च हुआ है। अब फिर मैं बता देता हूं। इसमे ंसे 12 करोड 58 लीाख रुपया तो हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बार्ड आदि को कर्ज के रूप में दिया गया है। 7 करोड 69 लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेन्ड फन्ड का सूद का है वह दिया गया है। यह हिसाब किताब में केवल लेन देन है। जो सडकें सैलब से खराब हो गई हैं उनके लिए पांच करोड रुपया मुरम्मत के लिए दिया गया है। 55 लाख रुपया भी सडकों की मुरम्मत और नयी सडकें बनाने के लिए दिया गया है। एक करोड 90 लाख रुपया गन्ने की सबसिडी है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कही पर डेढ रुपया और कही पर दो रुपये क्विंटल के हिसाब से सबसिडी दी गई है। 95 लाख रुपया हरिजनों की चौपालों के लिए रखा गया है। 54 लाख रुपया वह है जो पिछले साल पंचायतों के चुनाव हुए थे उनमें जिन पंचायतो ंके चुनाव सर्व सम्मति से हुए उनको पांच पांच हजार रुपया सरकार की ओर से दिया गया था। हमारी स्टेट में बहुत से गांवों में सर्व सम्मति से चुनाव हुए हैं जिसके कारण पार्टीबाजी

कम हुई है। इसके अलावा डेढ करोड रुपया वह है जो पिछले साल बजट के बाद सरकारी कर्मचारियों का डियरनैस अलाउंस का दिया गया है। अढाई करोड रुपया ि ाक्षा विभाग को दिया गया है। इसमें से 73 लाख रुपया कालेजिज को और 20 लाख रुपया स्कूलों की बिल्डिंगों की मुरम्मत के लिए दिया गया है। जो सैलाब से बिल्डिंगें खराब हो गई हैं। चालीस लाख रुपया कुरुक्षे. यूनिवर्सिटी को दिया गया है। उद्योग विभाग को पचास लाख रुपया दिया गया है इसमे से तीस लाख रुपया ऐसा है जो देहाती भाई बेकार हैं, उनको उद्योग लगाने के लिए दिया गया है। उन देहाती भाईयों को गवर्नमैंट की ओर से15 परसैंट सबसिडी भी दी जा रही है। मेरे साथियों को यहा ंहाउस में यह बताना चाहिए था कि फलां पद में इतना रुपया खर्च होना चाहिए था लेकिन गलत तरीके से गलत पद के लिए खर्च किया गया। इस प्रकार कोई भी सुझाव मेरे पास नहीं आया। कुछ रचनात्मक सुझाव श्री हरस्वरूप बूरा की तरफ से आये हैं और एक सुझाव श्री बीरेन्द्र सिंह जी की ओर से भी आया है। जहां तक चौधरी हरस्वरूप बूरा के सुझाव का संबंध है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कालेजों के लिए 43 लाख रुपया दिया है और 25 परसैंट से 75 परसैंट ग्रा।ट कर दी है लेकिन उसको उन्होंनें काफी नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि यू0पी0 पैट्रन होना चाहिए। यहां पर यह भी कहा गया था कि प्राईवेट कालेजों को सारे का सारा पैसा दिया जाना चाहिए। अगर उनकी यह बात मानी भी ली जाये तो जो प्राईवेट कालेज के लिए लोग कोि ा ा करते हैं दान इकट्ठा

करते हैं और जितना उनहेनं ि ाक्षा के क्षेत्र में काम किया है उतना नहीं कर पायेंगे। अगर उसमें सरकार का ज्यादा दखल होगा तो जितनी कोि ा ें प्राईवट कालेज वाले कर रहे हैं वे करनी छोड देंगें। हमारे यहां इतने बडे बडै कालेजिज हैं जैसे डी0ए0वी0 कालेज की संस्था है, सनातन धर्म संस्था है, सिक्ख कालेजिज हैं इन सभी की दान प्रणाली बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग उस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, इसलिए जान बूझ कर यह फैसला किया गया है कि 75 परसैंट ग्रांट का दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर लडकियों के कालेज हैं उनकी ग्रांट 84 परसैंट के करीब बन जाती है। दूसरी बात मूरा साहब ने यह भी कही कि इन कालेजेां के प्रोफैसरों की सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं है। मैनेजमैंट जब भी चाहे उन्हें निकला सकती है। उसके लिए बूरा साहब ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई अ योरैंस दी जानी चाहिए। मैं उनको बताना चाहात हूं कि इस बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है और इसी सै ान में प्राईवेट कालेजों के लिए भी बिल पे ा होगा और हमारी कोि ा ा है कि इसे पास करवाया जाये।

जहां तक प्राईवेट स्कूलों मे टीचर्ज की बात है, उनके लिए पहले से भी कानून बना हुआ है लेकिन कुछ दिक्कतें आई हैं उन पर विचार किया जा रहा है। मैं पक्का वायदा तो नहीं कर सकता कि वह इसी सैन् ान में सं ाोधन आयेगा लेकिन प्राईवेट

स्कूलों के टीचर्ज की जो दिक्कत है वह गवर्नमैंट के सामने है। वह इसी महीने या अगले महीने दूर हो जायेगी।

मुझे बूरा साहब की इस बात पर बडा ताज्जुक हुआ कि टयूबवैलों पर जो चारे की म ीनों लगी हुई हैं उन पर सौ रुपये टैक्स का देना पड़ता है। इस बात का खास तौर पर एलान किया जा चुका है कि टयूबवैलों पर जो चारे की म ीने लगी हुई हैं उन पर मोटर रेट के हिसाब से ही पैसे लिए जावेंगें यह बजट में एलान हुआ है। पक्कली नालियों के बारे में उन्होंने यहां पर सवाल उठाया। यह सवाल पहले भी उठाया जा चुका हैं यह बडा पेचीदा सवाल है इससे कोई संबंध नहीं रखता है। पक्की नालियों के लिए कोई रुपया नहीं लिया जा रहो वैसे यह सवाल सरकार के विचाराधीन है।

17.00 बजे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के बारे में यह विचार व्यक्त किया कि ये कौमर्ि यिल ढंग से नहीं चलायी जा रही हैं, मुझे अफसोस है कि हमारी पब्लिक अंडरटेंकिग्ज, कारपोरे ंज जैसे हरियाणा माइनर इरीगे ान टयूबवैल कारपोरे ान है या हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है और भिन्न भिन्न प्रकार की इसी तरह की 20—25 निगम/बोर्ड/कारपोरे ान हैं, एक आध का छोड कर किसी में भी मुनाफा नहीं है। आपको पता है कि हमारे हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 4 अरब

रुपया लगा हुआ है लेकिन मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले ही दिनों इस मामले में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए एक अलग से सैल कायम किया गयाहै जो इनकी देखभाल करेगा। जो निगम बिल्कुल ही घाटे में जा रही हैं और जिनकी उभरने की भी कोई गुंजाइ ा नही है उनके बारे में यह निर्णय लिया गया है कि उनको बंद कर दिया जाये। सरकार कोई इस बात में जिद्द नहीं करेगी कि इस निगम को जरूर चलाना है। अगर कोई निगम घाटे में है और उसका घाटा पूरा होने की कोई गुजांइ ा नहीं है तो हम उस निगम को बंद कर देंगे। जहां तक निगमों को कोमि ायल लाईंज पर चलाने का सवाल है, उसके लिए हमारी तरफ से पूरी कोि ा ा हो रही है। पिछले साल ही पब्लिक अडंरटेकिग्ज कमेटी बनाई गयी है। इसने भी बडा महत्वपूर्ण काम किया है। इस कमेटी से भी सलाह म ाविरा किया जायेगा और इन निगमों/कार्पोरे ान्ज/बोर्डों को कोमि ियल लाइंज पर चलाने की कोि ा ा की जायेगी। चोधरी भाम ोर सिंह जी ने एक सुझाव दिया कि भाहरों को जैसे अम्बाला भाहर को 5 लाख रुपये की ग्रांट दी गयी है। उसके बारे में मुझे यहां पर पिछले सै ान के दौरान में भी हाउस के काफी माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले थे। उस समय भी काफी एतराज किया गया था कि सिरसा और रोहतक की कमेटियों को एडहाक ग्रांट क्यों दी जा रही है ? माननीय सदस्यों का यह एतराज जायज है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपति नहीं है। मैं हाउस को यह

यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में पहले ही निर्णय ले चुकी है और सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात पर विचार करेगी कि किस भाहर में किस किस आधार पर रुपया दिया जाये और भविश्य में ऐसी एडहाक ग्रांट नहीं दी जायेगी। जो कसौटियां वह कमेटी तय करैगी कि वहां नालियां पक्की हैं या नहीं हैं, वहां पर सीवरेज है या नहीं है, उस आधार पर भविश्य में ग्रांटस दी जायेंगी।

लाटरी के मामले में डिप्टी स्पीकर साहब, काफी एतराज उठाया गया है। स्वामी जी को तो कुछ आंकडों में ही गलती लग जाती है मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि एक करोड 41 लाख रुपये की हमें आमदनी नहीं हुई बल्कि यह वह रुपया है जो टिकटों को छपाई, एजेंटों के कमी ान और सारे खर्चे मिलाकर एक साल में अंदाजा लगाया गया है। यह भी एक तजुर्बा हो रहा है। जब यह लाटरी दे ामें चली थी उस वक्त एक स्टेट ने पहले इसे भाुरू किया था। बाद में देखा देखी दूसरी स्टेटस ने भी इसे भाुरू किया। इस लाटर से भाुरू भाुय में हमारी स्टेट को काफी फायदा हुआ है। पहले साल तो हमें एक करोड रुपये का मुनाफा हुआच, फिर सवा करोड रुपये का लेकिन अब यह मुनाफा घटकर सिर्फ 18–20 लाख रुपया रह गया है। उस समय भी इस मामल में विचार किया गया था कि आया लाटरी को बंद कर दिया जाये या नहीं ? फिलहाल फैसला यही किया गया है कि इसे जारी रखा जाये। अगर इसमें कोई सुधार हो सकता तो यह जारी रहैगीं कुछ

गलतफहमी मेरे आनरेबल सदस्य स्वामी जी को है। जहां तक हरियाणा की जनता का ताल्लुक है हरियाणा की जनता कोई लाटरी की भौकीन नहीं हैं। कुल मिलाकर आये वर्श हरियाणा में सिफ 5–6 लाख से ज्यादा की टिकटें नहीं बिकती हैं हमारे एजेंट बम्बई में हैं,कलकते में हैं या दूसरी बाहर की स्टेटस में हैं जहां पर यह टिकटें ज्यादा बिकती हैं हमारा तजुर्बा यह है कि अगर हमारी 5–6 लाख से ज्यादा की टिकटें नहीं बिकती हैं और फिर भी 18–20 लाख रुपये की आमदनी हो जाये तो इसमे कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक नैतिक प्र न का ताल्लुक है जैसें मैंने बताया है कि इस साल भी इस बारे में विचार किया गया था, लेकिन अभी यह फैसला किया गया है कि फिलहाल यह चालू रहेगी। जहां तक रैडक्रास का ताल्लुक है डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि वह सदस्य जिन्होंने उसकी नुकताचीनी की है, वह यहां पर नहीं बैठे हैं। उन्होंने कह तो दिया कि इसे बंद कर दिया जाये लेकिन ऐसा मालूम होता है जो रैडक्रास को बंद करने की बात यहां पर कही गयी है, वह उन्होंने समझी नहीं ..... (व्यवधान)

एक आवाजः उन्होंने हरियाणा में रैडक्रास को बंद करने की बात नहीं कही है, उन्होंनें तो यह कहा है कि मेलों को बंद कर दिया जाये।

श्री मूल चन्द जैनः मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर अपोजी ान की तरफ से यह बात आयी थी कि मेलों को बंद कर

दिया जाये। उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मेलों में जुआ वगेरा खेला जाता है, वह तो बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन जहां तक रैडक्रास को बंद करने की बात का ताल्लुक है, मुझे अफसोस से यह कहना पडता है वह माननीय सदस्य यहां पर नहीं बैठे हैं। उनको पता नहीं है कि रैडक्रास से यह कहना पडता है, वह माननीय सदस्य यहां पर नहीं बैठे हैं। उनका पता नहीं कि रैडक्रास एक अन्तर्राश्ट्रीय संस्था है। यह लोगों को कितनी मदद देती है, यह भाायद उनको पता नहीं है। अगर किसी गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाये और वह अस्पताल में दाखिल हो और उसके पास पैसे न हों तो डिप्टी कमि ानर यह कर सकता है कि इसको दवाई की कमी की वजह से न करने दिया जाये, इसको रैडक्रास की तरफ से मदद दी जायेगी। यह रैडक्रास तमाम दुनिया के दे ाों में फैली हुई है। ..... (व्यवधान) ..... स्वामी जी ने कहा कि एक एम0एल0ए0 को तो 300 रुपये पैं ान मिले और एक बूढे आदमी को 15 से बढा कर 25 रुपये कर दी गयी है। उनके पढने में कसर रह गयी है। पहले 1–4–1977 तक 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कर दिया गया है। अगर किसी मां या बाप का बच्चा उसको स्पोर्ट नहीं करता, तो उसे यह पैं ान दी जाती है। आपको भाायद यह पता होगा कि यह पैं ान तहसीलदार की रिकमैंडे ान पर दी जाती है और अकसर 50 रुपये तक ही दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जाहं तक इनकी इस बात का ताल्लुक है कि प्रिटिंग वालो को कहिये। प्रिटिंग वालों को कोई कसून नहीं है। यह प्रिंटिंग की प्रणाली पढने की कसर हैं पहले 15 से लेकर

25 रुपये तक पैं ान मिल सकती थी जिसे अब बढाकर 25 रुपये से 50 रुपये कर दिया गया है। असल में स्वामी जी को यह गलतफहमी ही है। पैं ान या तो उस बूटें को दी जाती है जिसक आगे पीछे कोई न हो और उसके पास गुजारे का कोई साधन न हो या फिर उसको दी जाती है जिसके बच्चे उसको स्पोर्ट न करें। (व्यवधान) भला उस आदमी का एक मिलिट्री के आदमी से या किसी दूसरे रिटायर्ड आदमी से कैसे कम्पैरीजन किया जा सकता है जिसके पीछे पूरा एक परिवार रहता है जिसका पालन पोशण उसे करना पडता है। इसके अलावा स्वामी जी ने खास तौर पर एक बात कही कि एम0एल0ए0 होस्टल की कैंटीन के लिए 48 हजार रुपया दिया जा रहा है, वह नहीं देना चाहिए। इस मामले में मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि इस मामले में विचार किया जा रहा है कि चाहे एम0एल0ए0 होस्टल की कैंटीन है या हरियाणा भवन की कैंटीन है। हम इन सरी कैंटीनों को नो प्रोफिट नो लास बेसिज पर चलायें और सरकार की तरफ से कोई सबसिडी न दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी एम0एल0एज0 की अपने साथियों की एक बात की नुक्ताचीनी करते रहते हैं लेकिन उनकी कई नुक्ताचीनियां मिसकंसेपटिड होती हैं मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि एक एम0एल0ए0 अगर एक घंटे के लिए आता है तो उसको एक दिन पहले का और एक दिन बाद का डी0ए0 मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, रूल ऐसा है कि अगर कोई

एम0एल0ए0 एक दिन आता है और अगले दिन जाता है तो उस हालत में एक दिन पहले का और एक दिन बाद का भत्ता मिलता है। यह नहीं है कोई एम0एल0ए0 उसी दिए आए और उसी दिन चला जाए तो फिर भी उसे एक दिन पहले और एक बाद का डी0ए0 मिले। उसको तीन दिन का भत्ता नहीं मिलेगा। अगर स्वाती जी के पास कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई एम0एल0ए0 उसी दिन आया हो और उसने पहले दिन का टी0ए0 फार्म भरा हो तो वह बताएं। स्वामी जी पैं ान की बाबत भी कामी गलतफहमी है और मुझे ताज्जुब है कि स्वामी जी की कोई बता समझा भी दी जाए तब भी इनकी समझ में नहीं आती। इनका कहना है कि कोई एम0एल0ए0 एक दिन भी रह जाए तो उसको पैं ान मिल जाती है। इस बात की स्वामी जी बहुत नुक्ताचीनी करते हैं और मैंने बहुत दफा इनको समझाया है कि एक दिन के लिए कोई एम0एल0ए0 नहीं होता। अगर एक एम0एल0ए0 बनकर आ गया और उसका इलैक ान सैट ऐसाइड हो गया तो वह एक दिन के लिए भी एम0एल0ए0 नहीं रहता। उपाध्यक्ष महोदय, एम0एल0ए0 को पैं ान के बिल की ड्राफ्टिंग में उस समय कुछ कसर रह गई थी और इसी के कारण एक दिन की बात हो गई थी वरना एक दिन की बात नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम एमरजैंसी के दिनों में जेलों में थे तो एम0पीज0 की पैं ान का बिल पास हुआ था और चूंकि मैं मैम्बर पार्लियामैंन रह चुका था इसलिए मुझे खु ाी हुई कि कम से कम तीन सौ रुपया पैं ान के मिलेंगे तो हमारे बच्चों को कोई फिकर नहीं होगीं मेरा स्वामी जी को यह

कहना है कि आप गृहस्थी एम0एल0एज0 को अपनी कसौटी पर न परखें .....

स्वामी अग्निवे ा: आप यह तो मान रहें कि बिल की ड्राफ्टिंग में कसर रह गई थी। यह नहीं होना चाहिए कि एक दिन भी एम0एल0ए0 रह जाए तो वह भी पैं ान ले सकता हैं आप बताएं कि फार ऐनी पीरियड आफ टाईम का क्या मतलब है।

श्री मूल चन्द जैन: उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने हरिजनों के बारे में कहा है कि क्लास वन सर्विसिज में हरिजनों की परसैंट 2.5 प्रति ात है, क्लास टू सर्विसिज में 2.3 प्रति ात है क्लास तीन की सर्विसिज में 12.5 प्रति ात है और क्लास फोर सर्विसिज में बीस प्रति ात है जबकि सब सर्विसिज में बीस प्रति ात हरिजनों की परसैंट होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस कमी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। वे सदियों से पिछडे रहें हैं। अब वे लोग पढने लगे हैं। सरकान उनको हर तरह की सहुलियतें दे रही हैं। हरिजन बच्चों के लिये स्कूल और कालिज खोले जा रहें हैं ताकि वे वहां पर ट्रेनिंग लेकर कम्पिटी ान में आ सकें। जनता सरकार इससे ज्यादा ओर क्या कर सकती है कि 95 लाख रुपया जो सप्लीमैंटरी ग्रांटस के द्वारा मंजूर कराया जा रहा है, चौपालों के लिए रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बेचारे सदियों से पिछडे रहे हैं और इनको बैठने के लिये गांव में कोई जगह नहीं होती थी। अगर इनके यहां कोई भाादी वगैरह होती थी तो बडी मु कल सामने

आती थी। मैं कांग्रेस में रहा हूं और मैंने देखा था कि हजार दो हजार रुपया कई सालों के बाद चौपाल के लिये मिल जाया करते थे। कांग्रेस राज्य के तीस साल के भाासन में हरिजनों के लिये उतनी चौंपालें नहीं बनी जितनी कि पिछले तीन चार महीनों में बनी है। बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा चौंपाले बनी हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ये चौपालें न सिर्फ हरिजन भाईयों के लिये ही बनाई जाएंगी बल्कि जो बैकवर्ड क्लास के भाई हैं उनके लिये भी चौंपालें बनाई जाएंगी। मैं नहीं समझता कि कोई सरकार देहात के लिये और क्या कर सकती है जितना कि जनता सरकार कर रही है। अभी कल ही 15 तारीख को ग्रामीण औद्योगिकरण की योजना भाुरू की गई है और उसमें सभी मंत्री महोदय और एम0एल0एज0 भाामिल हुए थे। डिप्टी स्पीकर साहब, सह एक ऐसा नजारा था जिससे ऐसा मालूम होता था कि सच्चे मायनों में क्रांति आ गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक ऐसा जमाना भी था जिसमें बैंक लोगों को कर्जा नहीं देते थे लेकिन आज हालत यह है कि बैंक खुले आम लोगों को कर्जा दे रहे हैं। हमारी स्टेट में फ्लड रिलीफ का काम किया है वह तारीफ के काबिल है। हमारे सरकार कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछले साल भी हमारे यहां फल्ड आया था तब भी सरकार कर्मचारियों ने काबिले तारीफ काम किया था। अभी ओले पड़े थे। मैं तीन चार दिन हुए दस पन्द्रह गांवों में गया था और मुझे गांव के लोगों ने बताया कि हमारे यहां डिप्टी कमि नर आए थे, तहसीलदार आया था, एस0डी0एम0 आया और

इस बात की मुझे बडी खु ाी हुई कि हमारे सरकारी कर्मचारी लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह से भाोभा नहीं देता कि हम गैर जिम्मेदार की बात कहें या सरकारी कर्मचारियों को डिस्करेज करने की बात कहें। सरकारी कर्मचारी हमारे में से ही हैं। कोई हमारा रि तेदार है और कोई हमारा सगा सम्बंधी है। ये लोग कोई चीन या रूस से तो आए नहीं हैं। जो कमजोरियां हमारे अंदर मिनिस्टर के तौर पर हैं उसी प्रकार की कमजोरियां उनमें भी हो सकती हैं। अगर किसी प्रोग्राम को इम्पलीमैंट करने में कमी है तो वह पोलिटीकल बिल की है, पोलिटीकल लीडरि ाप की हें अगर पोलिटीकल किसी चीज को चलाना चाहे तो सरकारी कर्मचारी दो कदम आगे चलने को तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने देखा कि जब हमने फैसला कर लिया कि रूरल इंडिस्ट्रिलाइजे ान का प्रोग्राम चलाना है तो आपने देखा कि हमारे सरकारी कर्मचारी उस काम में जी जान से जुट गए। चीफ सैक्रेटरी ने बैंकों के एजेंटस की मीटिंग बुलाई और उनको लोगों की मदद करने के लिये कहा। इन सब बातों से पताच चलता है कि हमारे सरकारी कर्मचारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी सरकार कर्मचारियों का क्रिटिक रहा हूं लेकिन जहां पर क्रिटिसाइज करने की बात है वहीं पर करनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जब वे अच्छा काम कर रहे हों तब भी उनको डिस्करेज किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, भारत की बाकी स्टेटों का तो मुझे पतना नहीं लेकिन जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है 550 यूनिट पिछले डेढ साल में

देहात में लग चुके हैं और मुझे वि वास है कि हजारों की तादाद में और यूनिटस लग जाएंगे। इस काम में हमारे एम0एल0ए0 साहिबान ने कितनी दिलचस्पी ली है और यह वह खुद सोच सकते हैं। अगर अब तक 550 यूनिट लग चुके हैं और हजारों की तादाद में यूनिट और लगेंगे तो इसका क्रैडिट डिप्टी कमि नर, एस0डी0एम0 तथा दुसरे अफसरों को जाता है और इस स्कीम से हरियाणा की बेरोजगारी दूर होगीं अगर हमारे सदस्यगण इस काम में दिलचस्पी लेंगे तो हरियाणा का कल्याण होगा और हरियाणा में खु ाहाली बढती जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे कुछ प्वांयट थे और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कहने की आव यकता नहीं है .....

कामरेड भांकर लालः मैंने निगम और कार्पोरे ांज के बारे में कहा था लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री मूल चन्द जैनः उसके बारेम में मैंने बता दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक आनरेबल साथी चौधरी भाम ेर सिंह जी ने भी बोलते हुए काफी कुछ कहा, मुझे उनको सुनकर बडा ताजुब हुआ कि उन्होंने बोलने से पहले भाायद अच्छी तरह से पढा नहीं, अगर अच्छी तरह से पढकर बोलते तो वैल इंफार्मड क्रिटिसिज्म होता। उन्होंने केवल यह कहा कि दो लाख रुपये की रा ि ा केवल जुडी ि ायल स्टैम्पस के लिये ले रहे हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसके साथ नान जुडि ि ायल

स्टैम्प भी लिखा हुआ है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह कह दिया कि मुकद्दमेंबाजी ज्यादा हो गई है जिसके कारण यह जुडि ियल स्टैम्पस की सेल बढ गई है। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि जब कोई जमीनें बेचेंगें और दूसरे लोग खरीदेंगे तो कुदरती तौर पर नान जुडि ियल स्टैम्प वगैरह की सेल बढ जाएगी। अतः मैं उनको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह जो जुडि ियल स्टैम्पस की सेल का खच्र बढा है। वह केवल जमीनो ंके ज्यादा सौद वगैरह होने के कारण बढा है न कि मुकद्दमेबाजी के कारण ऐसा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं एक दो बातें और कह कर अपना स्थान लूंगा। यहां पर हरियाणा प्रदे ा में ओल पडने से जो नुक्सान हुआ उसका भी कई भाइयों ने जिकर किया। मेरे विचार में जितना रिलीफ इस हरियाणा सरकार ने ओलों से हुई तबाही के लिये लोगों को दिया है भाायद ही आज तक किसी और सरकार ने ऐसे रिलीु का एलान किया होगा (तालियां) जिन किसानों के पूरे के पूरे खेत नश्ट हो गये हैं या 75 परसैंट तक जिनकी बरबादी हो गई है उनको 300 रुपये प्रति एकड के हिसाब से रिलीफ दिया है जिनके खेत 50 परसैंट से 75 परसैंट तक बरबाद हो गये हैं, उनको 200 रुपये एकड और जिनके चौथाई से आधे खेत बरबाद हो गये हैं उनको 100 रुपया प्रति एकड के हिसाब से सरकार की तरफ से रिलीफ दी गई है। यह जो पैसा दिया गयाहै, यह नत तो हमारे बजट में प्रोवाइडिड था और न ही

मिने इस पैसे की मांग सप्लीमैंटरी ग्रांटस के द्वारा की है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दो करोड रुपये की रा ि ा देने का एलान कर दिया जो कि हमने अपने कंटिजेंसी ंफड में से दी हैं और इसके लिए हमने फाइनेन्ि ायल कमि नर को पावर दे दी है कि वह जिलों में इस पैसे का वितरण करवाएं। इस पैसे की स्वीकृति के लिये हम अपने हाउस के सामने आएंगे और यह डिमांड 79–80 की फर्स्ट इंस्टालमैंट में आयेगी, जिसका जिकर करना मैं अभी यहां पर बडा आव यक समझता था। इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मो ान को पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Quesion is-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause be clause.

स्वामी अग्निवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे वायदा किया था कि आप हिन्दी में बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आज नहीं, कल से कर लैंगे।

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Quesiton is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjorned till 2 p.m. on Monday, the 19th March, 1979.

***17.24 hrs.**

(The Sabha then*adjorned till 2 p.m. on Monday, the 19th March, 1979)